● वर्ष-5

● अंक-304

रायपुर, शुक्रवार
07 अगस्त 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6>> हिन्दू धर्म में सिंदूर का महत्व...

जेन जी भारत विरोधी नहीं हैं, बातचीत जरूरी: भागवत

मुंबई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भगवत ने गुरुवार को युवा पीढ़ी पर भरोसा जताते हुए कहा कि जेनरेशन जी और जेनरेशन अल्फा ईमानदार पीढ़ियां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीट परीक्षा के पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर पेलेट गन के इस्तेमाल के कारणों का अध्ययन किया जाना चाहिए। जंतर-मंतर पर पेलेट गन के इस्तेमाल के बारे में बात करते हुए भगवत ने कहा, लाठी हमला क्यों हुआ? पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और हमें इसके पीछे का कारण जानना होगा। भगवत ने यह भी कहा कि जब उनकी पीढ़ी आज की पीढ़ी की उम्र की थी, तब लोग बड़ों की बात सीधे-सीधे सुन लेते थे।

उन्होंने कहा, जब हम पीढ़ी की उम्र के थे, तब हम बड़ों की बात सुनते थे। हम कभी सवाल नहीं करते थे। अब पीढ़ी को तार्किक जवाब चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जेन जी और अल्फा ईमानदार पीढ़ियां हैं।

उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि जेन जी को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में, काम करने के तरीके और नियम होते हैं। डॉ। बी।आर। अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, अगर हम उनके दो भाषण भी पढ़ें, तो हमें पता चल जाएगा कि मुद्दों को कैसे सुलझाया जाना चाहिए।

राष्ट्र विरोधी कहना ठीक नहीं:जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से विरोध-प्रदर्शनों और इस बात पर चिंता के बारे में पूछा गया कि प्रदर्शनकारियों को राष्ट्र-विरोधी कहा जा सकता है, तो उन्होंने जेन जी और जेन अल्फा को संबोधित करते हुए कहा, मैं यह साफ करना चाहता हूं कि अगर जेन जी किसी आंदोलन में शामिल होती है, तो वे राष्ट्र-विरोधी नहीं हैं। वे हमारे अपने लोग हैं। वे हमारी अगली पीढ़ी हैं। बातचीत के लिए अपनापन और आपसी सम्मान की जरूरत होती है। हमें एक-दूसरे को समझने और सम्मान देने की जरूरत है। तभी सार्थक बातचीत हो सकती है, जिसमें हम उनकी चिंताओं को समझें और वे हमारे नजरिए को समझें। ऐसा ही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जेन जी या युवा पीढ़ी ऐसी है। मेरा मानना है कि आज की युवा पीढ़ी, यानी जेन जी और जेन अल्फा, मौजूदा पीढ़ी से अधिक ईमानदार है। इस पीढ़ी में देश के प्रति ईमानदारी, देशभक्ति की भावना और सेवा का जज्बा होना चाहिए।

सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी को करें वेरिफाई: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, नियम बनाना ठीक है, लेकिन वे तभी सफल होते हैं जब लोगों का नजरिया बदले। वरना, पहले से ही बहुत सारे कानून मौजूद हैं। कानून तभी असरदार होते हैं जब समाज उन्हें अपनाए।।। सोशल मीडिया पर आप क्या हैं, इस बारे में सोचना जरूरी है क्योंकि लोग आपके काम को ही फॉलो करते हैं। इसलिए, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप यह देखें कि आपके फॉलोअर्स आपके काम (सोशल मीडिया पर) को फॉलो करके किसी गलत रास्ते पर न चले जाएं। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि नकली वीडियो बनाए जा सकते हैं और आपके या मेरे नाम से झूठे बयान फैलाए जा सकते हैं। इसलिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय किसी भी कंटेंट पर तब तक भरोसा न करें जब तक कि उसे किसी भरोसेमंद स्रोत से वेरिफाई न कर लिया जाए। । हमें सोशल मीडिया के मामले में खुद पर अनुशासन रखना होगा। वरना, अगर आप किसी चीज पर बैन लगाते हैं, तो वह धोखाधड़ी वाले बाजार में चली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। टकराव के समय में, हमें अपनी सरकार के फैसलों के साथ चलना पड़ता है। लेकिन इससे पहले से बने रिश्ते नहीं टूटने चाहिए।

अब मानसून सत्र में विधेयकों पर सबकी नजर

नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू की दो दिनों की बातचीत के बाद भी संसद में सरकार और कांग्रेस के बीच गतिरोध बरकरार है। राहुल गांधी एफसीआरए और महिला आरक्षण व परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर सर्वदलीय बैठक की मांग पर अड़ गए हैं।

सर्वदलीय बैठक की जरूरत को नकारते हुए सरकार का कहना है की सभी दलों से बात हो चुकी है । एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों को पास कराने के लिए अगले एक-दो दिनों में फैसला ले लिया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगला हफ्ता अहम हो सकता है।दरअसल विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस से साथ चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार की ओर से बुधवार को गंभीर पहल शुरू हुई। किरेन रिजीजू और राहुल गांधी की लगभग 50 मिनट तक हुई मुलाकात में नेता प्रतिपक्ष ने सहयोगी दलों के सलाह-मशविरा के लिए समय मांगा।

गुरुवार को विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दलों की बैठक में सरकार की पहल पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया गया। फिर रिजीजू और राहुल गांधी के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की विपक्ष की मांग रख दी। जबकि किरेन रिजीजू का कहना था कि सरकार की पहले ही सभी दलों से बातचीत हो चुकी है, सिर्फ कांग्रेस के साथ बातचीत होनी है।एक वरिष्ठ मंत्री का कहना था कि तीनों विधेयकों की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार इसे हंगामे के बीच बिना चर्चा के पास कराने के पक्ष में नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अड़ियल रवैये के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। सरकार इन विधयकों से जुड़े सभी पक्षों से साथ बातचीत कर उनकी आशंका को दूर करने का प्रयास कर रही है।इसी सिलसिले में गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की एफसीआरए को लेकर ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों से लंबी चर्चा हुई। सरकार की ओर से साफ संकेत दिया गया है कि सिर्फ कांग्रेस के विरोध के कारण अहम विधेयकों को रोका नहीं जा सकता है। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कई विधेयक पारित किये जा चुके हैं।वहीं मौजूदा मानसून सत्र के सिर्फ पांच कार्यकारी दिन बच जाने को देखते हुए सत्र का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।

परिसीमन पर रिजिजू ने राहुल से मांगा समर्थन

संसद के लगभग तीन हफ़्ते तक ठप रहने के बाद, गुरुवार को किरेन रिजिजू ने फिर से राहुल गांधी से बात की। इस बातचीत में सदन में गतिरोध खत्म करने और महिला आरक्षण व परिसीमन के लिए

समर्थन बढ़ाने पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले पर सरकार से बातचीत करने से पहले वह इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों से सलाह-मशविरा करेंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार, बिल पास करने के लिए ज़रूरी संख्या पहले ही जुटाई जा चुकी है; हालाँकि, चूँकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए सरकार उन्हें भी साथ लाना चाहती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई। हमने उनसे एक खास मुद्दे पर बात की और दूसरे विषयों पर भी चर्चा की। हम कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ लगातार बातचीत बनाए रखना चाहते हैं और मिलकर काम करना चाहते हैं। हम भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हों, लेकिन दुश्मन नहीं हैं। इसलिए, हमें देशहित में मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि, बाहर ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि वे किसी भी कीमत पर संसद को चलने नहीं देना चाहते। लेकिन इससे नुकसान किसका होगा?

छत्तीसगढ़ की दो खिलाड़ी भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम में

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लिए खेल जगत से आज एक और बड़ी खुशखबरी आई है। बिलासपुर के खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की दो खिलाड़ियों गीता यादव और मधु सिदार का चयन भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ है। ये दोनों चीन के मोकी में आगामी 30 अगस्त से 13 सितम्बर तक होने वाले जूनियर एशिया कप में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रतिभा और दम दिखाएंगी।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने गीता यादव और मधु सिदार से वीडियो-कॉल पर बात कर भारतीय टीम में चयन पर बधाई दी। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को जूनियर एशिया कप हॉकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामना देते हुए उनकी तैयारियों की भी जानकारी ली। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और संचालक श्रीमती तनुजा सलाम ने भी दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जूनियर हॉकी टीम में चयनित ये दोनों ही खिलाड़ी प्रदेश की पहली आवासीय खेल अकादमी में वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री राकेश टोप्पो एवं मुख्य प्रशिक्षक श्री अजीत लकड़ा से हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

मधु सिदार हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले जशपुर जिले के कांसाबेल के छोटे से गांव पोंगरो की रहने वाली है। उनके माता-पिता कृषक हैं। वह सब-जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2024-25, स्कूल नेशनल 2024-25 तथा हरियाणा में सब-जूनियर इंटर जोन चैम्पियनशिप-2025 में भागीदारी कर चुकी हैं। उनकी टीम ने आंध्रप्रदेश में 1 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक आयोजित हॉकी इंडिया नेशनल चैम्पियनशिप में चतुर्थ स्थान हासिल किया था।

भारत का अग्नि प्रहार... 3000 किमी दूर बैठे दुश्मन को करेगी तबाह, टेस्ट सफल

नई दिल्ली। भारत ने अपनी सैन्य ताकत में एक और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ते हुए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड की देखरेख में किया गया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, मिसाइल ने अपने सभी तकनीकी और ऑपरेशनल पैमानों पर शत-प्रतिशत खरा उतरकर सफलता का परचम लहराया है।

बता दें कि अग्नि-4 को बेहद आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। इसमें पांचवीं पीढ़ी का ऑनबोर्ड कंप्यूटर और उन्नत एवियोनिक्स दिए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उड़ान के दौरान यदि रास्ते में कोई बाधा आती है, तो यह मिसाइल खुद-ब-खुद उसे पहचानकर अपना रास्ता ठीक करने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे भारत की सबसे भरोसेमंद रणनीतिक मिसाइलों में गिना जाता है।

मिसाइल का अचूक निशाना

इसके अलावा इस मिसाइल में खास नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इनकी बदौलत अग्नि-4 बिना किसी चूक के सीधे अपने लक्ष्य पर सटीक प्रहार करती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी यह सटीकता भारत की रक्षा और सामरिक ताकत को कई गुना बढ़ा देती है।

4000 डिग्री सेल्सियस की आग भी बेअसर

इन सभी ताकतों के अलावा, इस मिसाइल में एक और खास बात है, जिसके बदौलत ये मिसाइल आज के दौर में भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाने में सक्षम है। इस बात को ऐसे मसझिए कि दुश्मन के इलाके में घुसने पर जब मिसाइल वापस लौटती है, तो भयंकर गर्मी पैदा होती है। अग्नि-4 में लगी री-एंट्री हीट शील्ड ने कमाल दिखाते हुए करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तक के भारी तापमान को आसानी से झेल लिया। हैरानी की बात यह रही कि बाहरी सतह पर इतनी भीषण आग होने के बावजूद, मिसाइल के अंदर रखे संवेदनशील उपकरण बिल्कुल सुरक्षित रहे और भीतर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे बना रहा।

प्रमुख समाचार

राहुल गांधी की छात्रों की गूंज को लगा झटका

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए वेन्यू की मंजूरी वापस लिए जाने की आलोचना की और कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन को इस कार्यक्रम से क्या डर है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि पता नहीं वे किस बात से डरे हुए हैं। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए दी गई मंजूरी वापस ले ली है। यह कार्यक्रम 8 अगस्त को प्रयागराज के के.पी. ग्राउंड में होने वाला था। केपी कॉलेज के मैनेजमेंट ने एकेडमिक चिंताओं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड के इस्तेमाल की मंजूरी वापस ले ली। प्रयागराज की सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में, कायस्थ पाठशाला के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि यह फ़ैसला कॉलेज के प्रिंसिपल से बातचीत करने और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 अगस्त, 2025 के आदेश को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। इस आदेश में ज़ोर दिया गया था।

शुभेंदु सरकार ने आम जनता से मांगे दो साल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि राज्य अगले कुछ वर्षों में आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा और हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति करेगा। शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित मिलान मेला मैदान में एक वस्त्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए, अधिकारी ने घोषणा की कि वह 17 अगस्त को पुरुलिया में 4,000 करोड़ रुपये के इस्पात संयंत्र की नींव रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर महीने नई फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अगले एक-दो वर्षों में बंगाल आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा और हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति करेगा। हम एक महीने के भीतर कम से कम 25 उद्योगों को जमीन सौंप देंगे। अधिकारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार ने नए उद्यम स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण नीति शुरू की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी में उनसे हुई एक बैठक के दौरान इस बात किया।

हमने चोरी के खिलाफ आवाज उठाई है, भगवान राम पर नहीं

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी के मामले पर विपक्ष की आलोचना का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मंदिर से दान और कीमती सामान की कथित चोरी पर सवाल उठाने को राम-विरोधी होने जैसा नहीं माना जाना चाहिए। उनका यह बयान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के उस आरोप के बाद आया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर संसद में बार-बार यह मुद्दा उठाकर भगवान राम का विरोधी होने का आरोप लगाया था। इस आरोप का जवाब देते हुए राउत ने कहा कि राम मंदिर में चोरी हुई थी। क्या इसके लिए भगवान राम जिम्मेदार हैं? हमने चोरी के खिलाफ आवाज़ उठाई और अब हमें राम-विरोधी कहा जा रहा है। यह कैसा हिंदुत्व है? पैसे चोरी हुए, दान पेटियां लूटी गईं, यहां तक कि गहने और माता सीता का मंगलसूत्र भी कथित तौर पर चोरी हो गया। हमने ये मुद्दे उठाए और अब हमें राम-विरोधी करार दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को राम भक्त के तौर पर पेश किया जा रहा है।

अभिषेक बनर्जी के करीबी सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर रोक

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (पीए) सुमित रॉय को सलबोनी भूमि कब्जा मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि सुमित रॉय को जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा। इससे पहले 3 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला सलबोनी पुलिस द्वारा कथित सरकारी जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े की जांच से जुड़ा है। सुमित रॉय के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे, ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने आदेश दिया कि सुमित रॉय जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

तमिलनाडु कृषि बजट सिर्फ सीएम विजय की तारीफ : स्टालिन

चेन्नई। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार के कृषि बजट 2026 की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट किसानों की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहा और इसके बजाय इसका इस्तेमाल मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सत्ताधारी सरकार की तारीफ़ करने के लिए किया गया। एक्स पर एक पोस्ट में स्टालिन ने आरोप लगाया कि बजट में सूखे और कुरुवई खेती के मौसम के दौरान किसानों को हुए फसल के नुकसान जैसे अहम मुद्दों को नज़रअंदाज़ किया गया। स्टालिन ने कहा सूखे की समस्या को हल करने के बजाय, तमिलनाडु कृषि बजट 2026 का इस्तेमाल सिर्फ़ मुख्यमंत्री की तारीफ़ करने और उनकी चापलूसी करने के लिए किया गया। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के लिए सार्थक कदम उठाने के बजाय सरकार ने सिर्फ़ मौजूदा योजनाओं का नाम बदला है। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ़ नाम बदलने वाली सरकार बनकर रह गई है। क्या इस सरकार को लगता है कि अपनी योजनाओं पर विक्ट्री का लेबल लगाकर उसका काम पूरा हो गया।

हथकरघा: विकसित भारत के भविष्य की बुनाई

गिरिराज सिंह

किसी विकसित राष्ट्र का निर्माण सिर्फ तकनीक से ही निर्धारित नहीं होता। उसका खाका स्थायी खूबियों को भावी प्रगति के वाहक के रूप में बदल सकने की क्षमता से गढ़ा जाता है। अब जबकि हमारा देश 'विकसित भारत 2047' की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश कर रहे हैं, मैन्यूफैक्चरिंग को सुदृढ़ बना रहे हैं और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग को तैयार कर रहे हैं। फिर भी, हमारी हथकरघा परंपरा उन सबसे बड़ी खूबियों में से एक है जो हमेशा हमारे साथ बनी रही है। आगामी 7 अगस्त को जब भारत 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएगा, तो यह हथकरघा को एक ऐसे रणनीतिक क्षेत्र के तौर पर देखने का उपयुक्त अवसर होगा जो टिकाऊपन, प्रामाणिकता और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला को महत्व देने वाली दुनिया के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'विकसित भारत 2047' का सपना समृद्धि, आत्मनिर्भरता, समावेशिता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास पर आधारित है। हथकरघा, विरासत और नवाचार को एक साथ जोड़कर इस सपने को साकार करता है। साथ ही, यह महिलाओं के नेतृत्व में विकास, ग्रामीण उद्यमिता, आजीविका और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को भी बढ़ावा देता है। रामचरितमानस में कहा गया है, ×ह्वह्वश्वह्व;सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका॥ बल बिबेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे॥×ह्वह्वश्वह्व; विजय रथ के उपदेश में भगवान राम यह सिखलाते हैं कि स्थायी जीत शक्ति पर नहीं, बल्कि मूल्यों पर आधारित होती है। इन्हीं मूल्यों ने सदियों से भारत की हथकरघा परंपरा को टिकाए रखा है। हाथ से बुना हुआ हर कपड़ा परंपरा को बनाए रखने के साहस, हर धागे को बेहतरीन बनाने के धैर्य, ईमानदार कारीगरी की निष्ठा और पीढ़ियों से चली आ रही समझदारी को दर्शाता है। यही कारण है कि हथकरघा महज एक शिल्प नहीं, बल्कि भारत की महानतम सभ्यतागत खूबियों में से एक है। सबसे पहले कपास की खेती एवं बुनाई करने वाली सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैश्विकव्यापार में भारतीय वस्त्रों के दबदबे वाली अठारहवीं सदी तक, भारत ने वैश्विक स्तर पर वस्त्र निर्माण की उत्कृष्टता के सर्वोच्च मानक स्थापित किए। बंगाल के प्रसिद्ध मलमल के साथ-साथ बनारसी सिल्क, कांचीपुरम की बुनाई,

पोचमपल्ली इकत और अनगिनत क्षेत्रीय परंपराओं ने भारत को दुनिया भर में पहचान और प्रशंसा दिलाई। बंगाल का मलमल तो इतना महीन होता था कि 25 मीटर लंबा कपड़ा भी एक अंगूठी से होकर गुजर जाए। आज जब दुनिया प्रामाणिक, टिकाऊ और हाथ से बने उत्पादों की ओर मुड़ रही है, तो हमारे पास उस अग्रता को फिर से हासिल करने का एक ऐतिहासिक मौका है। हमारी अगली हथकरघा क्रांति के दौरान सिर्फ वस्त्र ही नहीं, बल्कि कारीगरी, विरासत, नवाचार और भरोसे का भी निर्यात होना चाहिए ताकि हाथ से बुना हर उत्पाद 'ब्रांड इंडिया' की पहचान बन सके।हथकरघा भारत का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। यह 35 लाख से अधिक बुनकरों व उनसे जुड़े कामगारों की आजीविका का सहारा है। इन कामगारों में से लगभग 72 प्रतिशत महिलाएं हैं। पिछले दशक में, सरकार ने 'कच्चा माल आपूर्ति योजना', 797 हथकरघा क्लस्टरों, 1.24 लाख से अधिक उन्नत करघों, लगभग 97,000 कारीगरों के कौशल विकास और उत्पादक कंपनियों, जीआई टैग वाले उत्पादों, हैंडलूम मार्क, इंडिया हैंडमेड सर्टिफिकेशन, अर्बन हाट और डिजाइन रिसोर्स सेंटर जैसी पहलों के रिए इस सेक्टर को सुदृढ़ किया है। आज 29 'बुनकर सेवा केन्द्र' प्रशिक्षण, कौशल के उन्नयन, डिजाइन के विकास, कच्चे माल संबंधी सहायता और बाजार से जोड़ने जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। वहीं, 11 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि उन्नत प्रशिक्षण के प्रसार को बढ़ाया जा सके और विशेष प्रकार के अधिक मूल्य वाले हथकरघा उत्पाद बनाए जा सकें। ये पहलें हथकरघा को सिर्फ एक कल्याणकारी गतिविधि के तौर पर समर्थन देने से हटकर, इसे वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी एवं रचनात्मक उद्योग के रूप में विकसित करने की दिशा में होने वाले एक बदलाव को दर्शाती हैं। आगामी 'राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम' 500 जिलों में 1,800 क्लस्टरों को सुदृढ़ करेगा, 65 लाख बुनकरों व कारीगरों को लाभान्वित करेगा और 'हैंडमेड इन इंडिया' को एक वैश्विक ब्रांड के तौर पर स्थापित करेगा। नवाचार हमेशा से भारत की हथकरघा से जुड़ी यात्रा का हिस्सा रहा है। महात्मा गांधी के अंबर चरखे ने सूत कातने के काम को आसान, तेज और अपेक्षाकृत अधिक कुशल बनाया। इससे आत्मनिर्भरता का विजन आगे बढ़ा। हाल ही में, असम के मैना करघे और शिवसागर में विकसित चित्तरंजन हथकरघे ने यह दर्शाया है कि करघे के बेहतर डिजाइन से बुनाई का काम कैसे आसान और अधिक उत्पादक हो सकता है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान के साथ मिलकर बनाया गया 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम टेक्नोलॉजी' ऐसे करघे विकसित कर रहा है।

खराब सड़कें, अधूरे विकास कार्य और मूलभूत सुविधाओं की कमी

जनप्रतिनिधियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, एसडीएम ने दिया भरोसा

एमसीबी। खोंगापानी नगर पंचायत में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों का आक्रोश एक बार फिर खुलकर सामने आया। खराब सड़कों, अधूरे विकास कार्यों और सुविधाओं की कमी से नाराज नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों ने नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी करने का ऐलान कर दिया। हालांकि प्रशासन के दखल और 10 दिनों के भीतर काम शुरू कराने के आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया गया है।

तालाबंदी की सूचना मिलने पर मनेन्द्रगढ़ एसडीएम लिंगराज सिदार नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष ललिता यादव और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में नगर पंचायत क्षेत्र की जर्जर सड़कों की मरम्मत, पेंडिंग विकास कार्यों को जल्द शुरू कराने और मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा की।

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया की नगर पंचायत क्षेत्र की ज्यादातर सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। सड़क पर बने गड्ढों से लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई विकास कार्य लंबे समय से अटके हैं। जनता में भी प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। जनप्रतिनिधियों ने यह भी याद दिलाया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने इन्हीं समस्याओं को लेकर सड़क पर बने गड्ढे में बैठकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय भी प्रशासन का ध्यान समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बावजूद हालात में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। लगातार अनदेखी के कारण इस बार नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी का निर्णय लिया गया। लंबी चर्चा के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी कि नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क मरम्मत सहित सभी आवश्यक विकास कार्यों की शुरुआत 10 दिनों के भीतर कर दी जाएगी। एसडीएम लिंगराज सिदार ने जनप्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश जारी किए जाएंगे और तय समय सीमा में कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।

प्रशासन के इस आश्वासन के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों ने फिलहाल तालाबंदी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर काम शुरू नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी सहित व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

सरगुजा खाद भंडारण केंद्र का कृषि मंत्री ने किया औचक निरीक्षण

अधिकारियों को दिए ये निर्देश

सरगुजा। प्रदेश के किसान खरीफ सीजन में खेती-बाड़ी के काम में जुटे हुए हैं। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर लगातार किसान और विपक्ष आवाज उठाती रही है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री राम विचार नेताम आज अचानक खाद भंडारण केंद्र पहुंचे। कृषि मंत्री ने औचक निरीक्षण कर खाद भंडारण की स्थिति चेक की और मौजूद अधिकारियों को जरुरी दिशा निर्देश जारी किए।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि खाद की वितरण केंद्रों तक समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने हिदायत भी दी है कि खाद को लेकर कोई भी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कहा, ये सरगुजा अंचल में हमारा डबल लॉक का केंद्र है। अंबिकापुर में और इसके साथ-साथ एक केंद्र सीतापुर में है तो यहां जो रेक पॉइंट है वहां से सीधे यहां पर खाद पहुंचाया जाता है। यहां के बाद हमारे सोसाइटियों तक खाद को पहुंचाने का काम होता है, तो हम यही देख रहे हैं कि कहीं पर हमारे किसानों के लिए कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। रामविचार नेताम ने कहा कि खाद के भंडारण को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। डीएपी की अगर दिक्कत होगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मंत्री ने बताया कि अभी तक 70 फीसदी डीएपी की मांग हम पूरी कर चुके हैं। रामविचार नेताम ने बताया कि जहां डीएपी की कमी थी उसे पूरा करने के लिए एनपीके का इस्तेमाल करने की सलाह हम लोग किसानों को दे रहे हैं। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है उनके सलाह से एनपीके के साथ-साथ और भी फर्टिलाइजर का उपयोग करने के लिए लोगों को निर्देशित किया जा रहा है।

महिला के जेवर लेकर भागे आरोपी, रास्ता पूछकर बातों में उलझाया

बिलासपुर। शातिर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को बातों में फंसाकर करीब दो लाख रुपये के सोने के जेवर ठग लिए। आरोपियों ने पहले बस स्टैंड का रास्ता पूछने के बहाने बातचीत शुरू की, फिर सुरक्षा का डर दिखाकर जेवर सुरक्षित रखने का झांसा दिया और कागज की पोटली थमाकर मौके से फरार हो गए। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेहरू चौक के पास की है। जानकारी के अनुसार सिंधी कॉलोनी निवासी विद्या मोटवानी सब्जी खरीदने के लिए बृहस्पति बाजार जा रही थी। इसी दौरान नेहरू चौक के पास ऑटो में सवार दो युवकों ने उनसे बस स्टैंड का रास्ता पूछा। बातचीत के दौरान कुछ ही देर में एक अन्य युवक भी वहां पहुंच गया। तीनों ने मिलकर महिला को अपनी बातों में उलझाया और ऑटों में बैठाया। आरोपियों ने महिला को यह कहकर डराया कि खुले में सोने के जेवर पहनकर चलना सुरक्षित नहीं है। चोरी या लूट की घटना हो सकती है। इसके बाद उन्होंने जेवर कपड़े में बांधकर सुरक्षित रखने की सलाह दी। महिला उनके झांसे में आ गई और अपने सोने के जेवर उन्हें दे दिए। आरोपियों ने जेवर को कपड़े में बांधने का नाटक किया। थोड़ी दूर जाने के बाद ठगों ने जेवर की जगह कागज की एक पोटली महिला को थमा दी और उसे ऑटो से उतारकर फरार हो गए।

कुछ देर बाद जब महिला ने पोटली खोली तो उसमें जेवर नहीं थे। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ। पीड़िता ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

शिक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी

चार लोगों को लगाया 9 लाख का चूना, पुलिस से की कार्रवाई की मांग

धमतरी। धमतरी जिले से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने समग्र शिक्षा में नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया और 9 लाख रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं मामले में कुटरचित चेक और फर्जी निफ्ट किए जाने का भी आरोप है। यह पूरा मामला मगरलोड थाना क्षेत्र का है। करेलीबड़ी निवासी हरिशचंद साहू ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि जुलाई 2025 में व्यवसायिक शिक्षक की परीक्षा के परिणाम को लेकर हुई हड़ताल के दौरान उसकी मुलाकात योगेन्द्र कुमार देवांगन से हुई थी। योगेन्द्र ने समग्र शिक्षा कंपनी में नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया और इसके लिए प्रति व्यक्ति ढाई लाख रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद उसने अपने दोस्तों देवेश कुमार साहू और पुलस्त कुमार खुरसुनी की नौकरी लगवाने के लिए भी योगेन्द्र से बात की। अगस्त 2025 से अलग-अलग समय में ऑनलाइन माध्यम से रकम भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। हरिशचंद के मुताबिक, जनवरी 2026 में उसका ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू हुआ, जिसके बाद उसका चयन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरतोरा के लिए हो गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चयन के बाद योगेन्द्र ने दोस्तों की नौकरी लगवाने और बाकी रकम देने की बात कही। शिकायतकर्ता का दावा है कि अलग-अलग ह्ह्ल स्कैनर और खातों के माध्यम से उसके और उसके दो दोस्तों के नाम पर कुल 6 लाख 39 हजार रुपये ऑनलाइन भेजे गए, जबकि 2 लाख 50 हजार रुपये नगद उसके घर करेलीबड़ी में लिए गए। इस तरह कुल रकम करीब 9 लाख रुपये होने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार, जब एक दोस्त की नौकरी नहीं लगने पर रकम वापस मांगी गई, तो मार्च 2026 में ढाई लाख रुपये का एक चेक दिया गया। आरोप है कि बैंक में चेक लगाने पर हस्ताक्षर का मिलान नहीं होने के कारण चेक कैंसिल हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर रकम वापस मांगने पर फर्जी ह्यस्त्रञ्ज के जरिए 50 हजार रुपये भेजे जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं बाकी रकम वापस करने के लिए 30 अप्रैल 2026 तक का समय मांगे जाने की बात आवेदन में कही गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, 1 मई को योगेन्द्र ने फोन कर घर आकर पैसा वापस लेने की बात कही। इसके बाद वह अपने भाई के साथ ग्राम सिरी पहुंचा, लेकिन आरोप है कि वहां रकम देने के बजाय गाली-गलौज की गई, जिसके बाद दोनों वापस लौट आए। हरिशचंद ने अपने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि रकम वापस नहीं करनी पड़े, इसलिए उसके और उसके दोस्तों के खिलाफ चोरी, धमकी और अवैध वसूली समेत अन्य शिकायतें की गई हैं। अब शिकायतकर्ता ने पुलिस से पूरे मामले की जांच कर नौकरी लगाने के नाम पर कथित ठगी, कुटरचित चेक और कथित फर्जी ऋ्रस्तर रसीद के मामले में योगेन्द्र कुमार देवांगन के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है।

गुरुकुल' में नाबालिग छात्रा के बच्चे को जन्म देने का मामला तूल पकड़ा, एसआईटी जाचं की मांग

कवर्धा। शहर के एक निजी आवासीय स्कूल 'गुरुकुल' में पढ़ने वाली 10वीं की नाबालिग छात्रा द्वारा बच्चे को जन्म देने का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। आरोपी के खिलाफ बीजापुर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब गुरुकुल पब्लिक स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली और हॉस्टल की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आदिवासी विकास परिषद ने एसआईटी जांच की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।

सरकारी उत्कर्ष योजना के तहत बीजापुर की एक नाबालिग छात्रा कबीरधाम के निजी स्कूल के हॉस्टल में रहकर 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। आरोप है कि छुट्टियों के दौरान गांव में उसके साथ अनाचार हुआ। इसके बाद वह करीब आठ महीने तक स्कूल हॉस्टल में रही। प्राचार्य के अनुसार, 5 फरवरी को तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे घर ले गए और 12 फरवरी को उसने बच्चे को जन्म दिया। मामले में आरोपी के खिलाफ बीजापुर जिले के थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल स्कूल की निगरानी व्यवस्था पर है। आखिर आठ नौ महीने तक हॉस्टल में रह रही छात्रा की गर्भावस्था की जानकारी किसी को कैसे नहीं हुई? क्या वार्डन, महिला स्टाफ या प्रबंधन को इसकी भनक नहीं लगी? और जब छात्रा की तबीयत बिगड़ी तो क्या स्कूल स्तर पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया? इन्हीं सवालों के जवाब अब जांच से सामने आने हैं।

इस स्कूल का नाम पहले भी एक नाबालिग छात्रा से जुड़े कथित अनाचार के मामले में सामने आ चुका है। उस समय स्कूल के एक कर्मचारी और तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई हुई थी। ऐसे में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, किसी भी संस्थागत लापरवाही की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

इस संबंध में प्राचार्य मनोज राय ने कहा कि यह घटना उनके कार्यकाल से पहले की है। उन्होंने बताया कि छात्रा को परिजन अपने साथ ले गए थे, और बाद में परीक्षा नहीं देने की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य सवालों पर उन्होंने तत्कालीन प्राचार्य को ही जवाब देने वाला बताया।

आदिवासी विकास परिषद के कामू बैगा ने आरोपी के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिषद का कहना है कि यदि छात्रा लंबे समय तक हॉस्टल में रही, तो निगरानी व्यवस्था की भी जांच होनी चाहिए। संगठन ने एसआईटी गठित करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। फिलहाल, आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन अब नजर इस बात पर है कि जांच केवल आरोपी तक सीमित रहती है या स्कूल प्रबंधन की भूमिका और हॉस्टल की निगरानी व्यवस्था की भी निष्पक्ष जांच होती है। क्योंकि स्कूल सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी भी है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

अतिक्रमण कर रखे कबाड़ को हटाने का दिया निर्देश

लोरमी। नगर के वार्ड क्रमांक 12 कुंदरापारा में कोतरी नाला और महामाया मंदिर के समीप हो रहे अवैध अतिक्रमण की खबर प्रकाशित होने के बाद राजस्व व नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्काल कबाड़ को हटाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, कुंदरापारा के निवासियों ने दो दिन पूर्व ही महामाया मंदिर के पास अवैध कबाड़ी के भंडारण और नाले व शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर गौशाला निर्माण किए जाने की शिकायत एसडीएम से की थी। एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार और नगर पालिका सीएमओ अपनी पूरी प्रशासनिक टीम और अमले के साथ खुद मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण करते हुए महामाया मंदिर के बगल में संचालित अवैध कबाड़ी के काम को तत्काल प्रभाव से हटाने के कड़े निर्देश दिए हैं।वहीं, कोतरी नाला के समीप अतिक्रमण कर बनाए गए गौशाला को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने न्यायसंगत और संवेदनशीलता भरा रुख अपनाया। गौशाला संचालक को कुछ दिनों की मोहलत दी है, ताकि गायों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा सके।

पेट्रोल-पंप कर्मचारी पर हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर। जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल की उधारी की रकम लेने पहुंचे कर्मचारी पर कुछ लोगों ने हमला किया था। जानकारी के अनुसार प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी रविंद्र रजक उधार दिए गए पेट्रोल की रकम लेने दुकान पहुंचा था। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद लोग आपस में तेज आवाज में बातचीत कर रहे थे, जिसे लेकर पड़ोसियों ने आपत्ति जताई। इस पर जब रविंद्र रजक ने जवाब दिया तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से रविंद्र रजक पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घायल कर्मचारी को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया।

सरगुजा में एमपी की शराब खपाने की कोशिश, दो गिरफ्तार

सरगुजा। अंबिकापुर में अवैध शराब बिक्री के मामले में आबकारी की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम ने एमपी के शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एमपी की शराब लाकर सरगुजा में खपाने का प्रयास कर रहे थे। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना उदयपुर अंतर्गत भदवाही निवासी गौरव जायसवाल भारी मात्रा में एमपी राज्य की शराब लाकर ग्राम नुनेरा के पंच बृजलाल पैकरा के घर में रखा है। पूछताछ में बताया कि उसके घर में रखा माल भदवाही निवासी गौरव जायसवाल का है। इसके बाद आरोपी के बयान के आधार पर टीम बृजलाल के साथ गौरव जायसवाल के घर पहुंची। गौरव जायसवाल ने कबूल किया कि बृजलाल के पास जो माल मिला वो उसका ही है। उक्त मामले में आबकारी उड़नदस्ता टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36, 59(क) के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बिहारपुर तहसीलदार की कार ने मारी एसयूवी को टक्कर

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के बिहारपुर थाना क्षेत्र में तहसीलदार से जुड़े एक सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला. बिहारपुर थाना के सामने उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब बिहारपुर के तहसीलदार की कार ने सड़क किनारे खड़ी एक एसयूवी वाहन को टक्कर मार दी।हादसे में एसयूवी क्षतिग्रस्त हो गई।घटना के बाद वाहन मालिक और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। क्षतिग्रस्त एसयूवी के मालिक गोरखनाथ पाठक ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, तभी तहसीलदार की कार ने उसे टक्कर मार दी।उनका यह भी आरोप है कि जब उन्होंने घटना का विरोध किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण बिहारपुर थाना पहुंचे और थाना परिसर के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने तहसीलदार के खिलाफ निष्पक्ष जांच, मेडिकल परीक्षण कराने तथा उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।

बिलासपुर केंद्रीय जेल का जायजा लेने पहुंचे डीजी

बिलासपुर। बिलासपुर जेल महानिदेशक (डीजी जेल) हिमांशु गुप्ता ने बिलासपुर स्थित केंद्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कैदियों की समस्याएं सुनीं और जेल के सुदृढ़ीकरण और कैदियों के कल्याण के लिए विभिन्न आधुनिक सुविधाओं की स्वीकृति दी। इस दौरान डीआईजी जेल एसएस तिग्गा,जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी, जेल चिकित्सक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें की बीते दिनों सेंट्रल जेल में बंद उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी ने गर्म भट्टी में कूदकर जान दे दी थी। निरीक्षण के दौरान डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने एक अनोखी पहल करते हुए कैदियों की अंग्रेजी की क्लास ली। उन्हें पढ़ाई और भाषा सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने कैदियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। जेल में उद्योग संचालन के लिए कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट निर्माण सिखाया गया।

बिजली समस्या से जूझ रहे तोयलंका के ग्रामीण

दंतेवाड़ा। दक्षिण बस्तर के सुदूर और दुर्गम क्षेत्र स्थित तोयलंका गांव के ग्रामीण पिछले तीन महीनों से बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। गांव में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप होने के कारण पूरा गांव अंधकार में डूबा हुआ है। इससे ग्रामीणों का दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाई और बिजली व्यवस्था शीघ्र बहाल करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले तीन महीनों से गांव में बिजली नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शाम होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। अंधेरे के कारण सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा लगातार बना रहता है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की और गांव की समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी।विभागीय स्तर पर समाधान नहीं मिलने के कारण आखिरकार ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का रुख किया और अपनी समस्या को प्रशासन के सामने रखा।

बिजली नहीं होने से मोबाइल फोन चार्ज करना भी मुश्किल हो गया है।संचार व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ रात के समय सुरक्षा की समस्या भी बढ़ गई है। गांव में छोटे व्यवसाय, घरेलू कार्य और विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल बिजली बहाल कराने की मांग की ताकि सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर लौट सके।ग्रामीणों की बात गंभीरता से सुनने के बाद कलेक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि समस्या का शीघ्र समाधान कराया जाएगा।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने और गांव में जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कराने का आश्वासन दिया।

फौजी भाइयों के लिए बना रहीं गोबर-बीज से सजी राखी

जांजगीर-चाम्पा। जिला में रक्षाबंधन की तैयारी शुरू हो गई है, राखियों से बाजार सज गया है, और बहनें अपने भाइयो की कलाई में राखी सजाने और भाई की लम्बी उम्र की कामना के लिए राखी खरीद रही हैं, लेकिन चाम्पा की एक महिला अपने बच्चों और सहेलियों के साथ चार साल से बार्डर में तैनात फौजी भाइयों के राखी तैयार कर रही हैं। ये राखी अपने आप में इसलिए भी अनूठा है, क्योंकि यह रेशमी धागा के साथ मिट्टी, गोबर और बीज को मिलाकर बनाया जा रहा है, और राखियों के साथ तिलक के लिए मिट्टी भी भेजने की तैयारी है।चाम्पा की रहने वाली नेहा अविनाश अग्रवाल वैसे तो मारवाड़ी महिला समिति के माध्यम से समाजसेवा के क्षेत्र में कुछ न कुछ करती रहती हैं, लेकिन चार वर्ष से नेहा अग्रवाल ने देश की रक्षा में जुटे बार्डर में तैनात फौजी भाइयों के लिए रक्षाबंधन भेजने की शुरुआत की है। नेहा अपनी सहेलियों से साथ मिलकर राखी तैयार कर रही हैं, और सजाने के लिए तिरंगा पट्टी के साथ मिट्टी, गोबर और बीजों का इस्तेमाल करती हैं। नेहा अविनाश अग्रवाल का मानना है कि देश की मिट्टी से फौजी भाइयों का विशेष लगाव होता है। भारत माता की रक्षा के लिए फ़ौजी हर मौसम मे तैनात रहते हैं, राखी जैसे अवसरों पर परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी नहीं हो पाती। ऐसे में नेहा और महिला समिति ने मिट्टी, गोबर और अलग-अलग फल-फूल के बीजों से राखी बनाती हैं, और उन्हें भारत के नक्शा कर स्वरूप देकर तिरंगा फीता से चिपका कर सूखाकर एकत्र करती हैं। वे बताती हैं कि इसका मूल मकसद राखी की खुशियाँ और फौजी भाइयों की लम्बी उम्र की कामना के साथ पौधारोपण के लिए प्रेरित करना भी है। इस राखी में मिट्टी और गोबर के साथ डाले गए फल-फूल को राखी के बाद निकाल कर एक गमला में एकत्र करना, उससे निकलने वाली पौधों को सहेज कर रखने की कामना करते हैं।

संक्षिप्त समाचार

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मिलावटखोरों को दी चेतावनी

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दूध, दही अथवा मक्खन में मिलावट करने वालों को आगाह करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। हम एनालॉग पनीर ही नहीं, सभी खाने-पीने की चीजों में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से चर्चा में रेलवे स्टेशन में 500 किलो पनीर जब्ती के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर कहा कि विभाग को दिक्कत होती है। रेलवे परिसर में कोई वारदात हो या कोई घटना हो, तो रेलवे कार्रवाई में आता है। इसके बाद भी मैं सभी को कहना चाहता है कि वो काम करने में डाल-डाल हैं, तो हम पाट-पाट है। हम लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्टूडेंट से मुलाकात हुई थी। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है। इस विषय पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। मामले में विचार किया जा रहा है। 2028 चुनाव में कांग्रेस के जीत के दावे पर श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के एक पॉकेट में पेट्रोल, तो दूसरे में माचिस है। पंजाब में कांग्रेस के नेताओं में घमासान हो रहा है। कांग्रेस कभी एक होकर काम नहीं कर सकती। कांग्रेस केवल प्लान बनती है, एक्शन नहीं कर सकती। अपने मन को तसल्ली के लिए कांग्रेस बहला लेती है।

तकनीकी खराबी के कारण उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट अस्थायी रूप से ठप

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://highereducation.cg.gov.in/) पर सर्वर संबंधी तकनीकी समस्या के कारण उपयोगकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट वर्तमान में अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। मिली जानकारी के अनुसार, यह समस्या वेबसाइट के स्सरु (सिक्योर सॉकेट्स लेयर) सर्टिफिकेट से जुड़ी तकनीकी त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई है। इस सिक्योरिटी एरर की वजह से छात्र और अन्य उपयोगकर्ता पोर्टल का सुरक्षित रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने इसका तत्काल संज्ञान लिया है और सुधार कार्य शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की तकनीकी टीम स्सरु सर्टिफिकेट के नवीनीकरण और सिस्टम री-कॉन्फ़िगरेशन के काम में लगी हुई है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खामी को जल्द से जल्द दूर करने के प्रयास जारी हैं। जैसे ही मेंटेनेंस का काम पूरा होगा, वेबसाइट की सभी ऑनलाइन सेवाएं और सुविधाएं पूर्ववत चालू कर दी जाएंगी।

प्रतिबंधित एनालॉग पनीर जब्त, डेयरी का लाइसेंस निलंबित

रायपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा रायगढ़ जिले में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत बुधवार को कई डेयरियों में आकस्मिक निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग नियंत्रक के निर्देश पर सतगुरु डेयरी का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान वहां से 07 किलोग्राम प्रतिबंधित एनालॉग पनीर बरामद हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पनीर का नमूना जांच हेतु संग्रहित किया तथा शेष पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर डेयरी का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सुधार सूचना नोटिस जारी की गई। जांच दल ने इसके बाद कस्तूरी डेयरी, सुरभि डेयरी, मुन्ना डेयरी सहित कोड़ातराई एवं पटेलपाली स्थित सतीश एवं मनोज मशरूम डेयरी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सतीश पटेल के प्रतिष्ठान से 08 किलोग्राम एक्सपायरी खोवा बरामद हुआ, जिसे ओडिशा से लाया गया था। अधिकारियों ने उक्त खोवे को मौके पर ही नष्ट कराते हुए संबंधित संचालक को नोटिस जारी किया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलेभर में इस प्रकार की विशेष जांच एवं कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। इस कार्रवाई में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेमीचंद पटेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी शांतनु भट्टाचार्य तथा नमूना सहायक सुमन अग्रवाल उपस्थित थे।

11 कार्यों के लिए 1.52 करोड़ मंजूर, साव के अनुमोदन के बाद स्वीकृति आदेश जारी

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बीजापुर जिले के भैरमगढ़ नगर पंचायत में 11 कार्यों के लिए कुल एक करोड़ 52 लाख 14 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भैरमगढ़ नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-3 में बेलतीपदर रोड से आंगनबाड़ी केंद्र तक और वार्ड क्रमांक-14 में बाजार स्थल से पुसनार पहुंच मार्ग सहित 6 सी.सी. सड़कों के लिए कुल एक करोड़ 12 लाख 75 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से वार्ड क्रमांक-2, वार्ड क्रमांक-11, वार्ड क्रमांक-12 और वार्ड क्रमांक-13 में भी सी.सी. सड़कों के निर्माण कराए जाएंगे। विभाग ने भैरमगढ़ नगर पंचायत में पांच आर.सी.सी. नालियों के निर्माण के लिए 39 लाख 39 हजार रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से शहर के वार्ड क्रमांक-8 और वार्ड क्रमांक-13 में एक-एक तथा वार्ड क्रमांक-15 में दो नालियों के निर्माण शामिल हैं।

विकसित भारत जी राम जी, सीएम साय ने बताई खूबियां

■ **26 जनवरी तक तीन अभियान पूरे करने पर जोर**

रायपुर। वीबी जी राम जी को लेकर सीएम विष्णुदेव ने जानकारी दी। विकसित भारत जी राम जी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी को मालूम है कि 1 जुलाई 2026 से हमारे देश में विकसित भारत जी राम जी योजना प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए हम पीएम नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। ये योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं है बल्कि ग्रामीण विकास,जल संरक्षण, आधारभूत संरचना और कृषि आजीविका को भी सशक्त बनाने की पहल है। इस योजना के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री की संकल्पना है कि देश को 2047 तक विकसित भारत के तौर पर खड़ा करने का। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका योजना निभाएगी।

जो भी पंजीकृत श्रमिक हैं उनकी डिमांड पर 125 दिन का रोजगार स्वीकृत होगा। इसके लिए मौजूदा फाइनेंसियल ईयर में राज्यांश सहित 5191 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके पहले तीन महीने तक इस फाइनेंसियल ईयर में रोजगार गारंटी का भी काम चला। जिसमें 1 हजार 264 करोड़ रुपए के काम तीन महीने में हुए। ये 1 जुलाई से ये लागू हुआ है। अब तक फाइनेंसियल 6855 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश को मिल रहा है। जो अब तक का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार एवं विकास के लिए वित्तीय निवेश है। इसके लिए हम एक बार फिर प्रधानमंत्री का आभार करना चाहेंगे।

प्रथम किस्त के तौर पर हमारे प्रदेश को 1538 करोड़ 93 लाख की राशि मिल चुकी है इसमें एक और खूबी है इसमें जो नरेगा की मजदूरी 261 रुपए प्रतिदिन थी उसे बढ़ाकर 300 रुपया किया गया है। 39 रुपया की बढ़ोतरी इसमें प्रतिदिन हुआ है जिसका लाभ हमारे मजदूरों को मिलेगा। इस योजना के तहत इसमें कृषि प्रधान देश में बड़ा निर्णय लिया गया है जिसमें साल में 2 माह तक ये योजना बंद रहेगी इन दो महीनों में खेती किसानी करने वाले लोगों को मजदूर आसानी से मिल जाएंगे। इससे खेती कार्य करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी इस योजना में एक और खूबी ये भी है कि इस योजना में कुल 318 तरह के काम होंगे। विष्णुदेव साय ने कहा इसमें चार

श्रेणियों में काम होंगे इसमें जल सुरक्षा काफी प्राथमिकता दिया गया है। विकसित भारत में 107 तरह के जल संरक्षण और जल संरचना से जुड़े काम होंगे। इसी तरह ग्रामीण अधोसंरचना के तहत 90 तरह के काम होंगे। गांव में आजीविका संवर्धन के लिए 86 प्रकार के काम इस योजना के तहत लिए जा सकेंगे जलवायु अनुकूल एवं आपदा प्रबंधन के कार्य इस योजना के तहत 35 तरह के काम लिए जा सकेंगे इसमें प्राकृतिक आपदा, बाढ़, जंगल में आग जैसी चीजों के लिए इस योजना के तहत काम लिए जा सकेंगे।

पहला अभियान- हर स्कूल में शौचालय

15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक मेरी बेटी मेरा अभिमान नाम से अभियान चलेगा। 6671 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण होगा इसमें कुल 286.85 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

दूसरा अभियान- मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय निर्माण

पूरे प्रदेश में 6534 मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय का निर्माण करेंगे इसके एक यूनिट का लागत 6 लाख होगा। 549 ऐसी जगह है जहां सिर्फ मुक्तिधाम बनाने की आवश्यकता है इसमें 18.22 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह से 26 जनवरी 2027 तक प्रदेश के सभी गांव में मुक्तिधाम और शेड का निर्माण हो जाएगा साथ ही शासकीय स्कूल में बच्चियों के लिए शौचालय का निर्माण होगा।

तीसरा अभियान - मोर गांव मोर पानी

इस अभियान की शुरुआत 24 अप्रैल 2025 में किए थे। इसके तहत 50 हजार से ज्यादा जल संरक्षण केतहत काम हुए हैं । 50 हजार जगहों पर काम बाकी है। 10 हजार 27 ड्राइ हैंडपंपों की पहचान करके इसे रिचार्ज किया जाएगा। रिचार्ज करने के एक यूनिट में 52 हजार का खर्च आएगा। इसके लिए 52.14 करोड़ की स्वीकृति होगी।

पिछला बकाया का हो रहा भुगतान

सीएम साय ने कहा कि पहले नरेगा में काम पहले होता था और पैसा बाद में आता था लेकिन अब एडवांस में हमारे पास पैसा आ चुका है मजदूरों को हम कहना चाहेंगे कि मजदूरी भुगतान में देरी नहीं होगी। और पिछला बकाया 450 करोड़ रुपए में से 395 करोड़ का भुगतान हो चुका है। बाकी एक हफ्ते में हो जाएगा। ग्राम पंचायतों से कहना चाहूंगा कि जो तीन अभियान हैं उसके कार्य का प्रस्ताव जनपद पंचायत में जमा करें,उन्हें कामों की स्वीकृति शीघ्र अति शीघ्र मिल जाएगी।

इससे पहले सीएम साय ने प्रेसवार्ता में देर से आने पर खेद जताया उन्होंने बताया कि वो एक दूसरी मीटिंग में थे,जिसके कारण विलंब हुआ है। उन्होंने प्रेसवार्ता से पहले गृहमंत्री विजय शर्मा जी,एसीएस पंचायत रिचा शर्मा और जी राम जी के कमिश्नर का स्वागत किया।

हरेली तिहार के पोस्टर पर सियासत

कांग्रेस ने लगाया छत्तीसगढ़ महतारी की उपेक्षा का आरोप, भाजपा ने बताया मानवीय भूल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हरेली तिहार के पोस्टर को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रायपुर में हरेली को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो गायब है। एक ओर जहां कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी की उपेक्षा और सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है, तो वही दूसरी ओर भाजपा ने इसे मानवीय भूल बताया है।

कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हरेली छत्तीसगढ़ की पहचान, संस्कृति और अस्मिता का पर्व है। पूरे रायपुर में हरेली के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए, लेकिन उनमें कहीं भी छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र दिखाई नहीं दिया। छत्तीसगढ़ महतारी की उपेक्षा, करोड़ों छत्तीसगढ़वासियों की भावनाओं को ठेस

पहुंचाने वाली बात है।

कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक पर्व है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी पोस्टर में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को स्थान नहीं दिया गया। भाजपा प्रदेश के पारंपरिक त्योहारों को पहले महत्व नहीं देती थी और अब जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की पहल के बाद इन त्योहारों को मनाया जा रहा है, तब भी छत्तीसगढ़ महतारी को सम्मान नहीं दिया जा रहा। पोस्टर से छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर हटाना भाजपा की छत्तीसगढ़ विरोधी सोच और मानसिकता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि यह मानवीय भूल है उसे ठीक कर लिया जाएगा। कांग्रेस को इसमें कहने की जरूरत नहीं है। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। वही उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने इसे नशे का गढ़ बनाया था, खून का गढ़ बनाया था, युवाओं को नशे में धकेला है। हम छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान करते हैं। इसे ठीक कर लिया जाएगा।

मंत्रालयीन कर्मचारी संघ को लगा झटका

तमाम विरोध के बावजूद उप सचिव अंशिका पाण्डेय का प्रकरण नस्तीबद्ध

रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ को बड़ा झटका लगा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थापना शाखा में लंबे समय से पदस्थ उप सचिव अंशिका ऋषि पाण्डेय के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों को दरकिनार करते हुए इस पूरे प्रकरण को नस्तीबद्ध (बंद) कर दिया है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने 23 जून पत्र और उसके बाद 22 जुलाई को स्मरण-पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा था। संघ का आरोप था कि अंशिका पाण्डेय पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय से एक संवेदनशील सीट पर जमी हुई हैं, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के ही स्थानांतरण नियमों (3 वर्ष की अधिकतम अवधि) का खुला उल्लंघन है।

संघ ने अपने ज्ञापनों में अंशिका पांडेय पर

पर गंभीर आरोप लगाए थे. कर्मचारी संघ का दावा है कि उनके पास इन सभी आरोपों के संबंध में अत्यंत पुख्ता और प्रामाणिक साक्ष्य मौजूद थे, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए वे तैयार थे। परंतु राज्य में लागू सुशासन व्यवस्था को दरकिनार करते हुए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संघ से इन साक्ष्यों को लिए बिना ही मामले को रफा-दफा कर दिया गया।

सरकार द्वारा की गई इस एकतरफा कार्रवाई से मंत्रालयीन कर्मचारियों के मध्य भारी असंतोष और निराशा का माहौल है। कर्मचारियों का मानना है कि प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता की बात करने वाली शासन व्यवस्था में इस प्रकार से शिकायत को दबाना सुशासन की दावों की पोल खोलता है।

आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन

शराब दुकानों में गड़बड़ी पर दो आबकारी उपनिरीक्षक निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में अधिक कीमत पर बिक्री और अन्य गंभीर अनियमितताओं के मामलों में आबकारी विभाग ने एक ही दिन तीन बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बलौदाबाजार-भाटापारा और बालोद के दो आबकारी उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि 53 पेटी अवैध शराब प्रकरण में बालोद की सहायक जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा शासन को भेजी गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की रोहासी देशी कम्पोजिट शराब दुकान में अधिक कीमत पर शराब बिक्री की शिकायत पर मूल शिकायत के अनुरूप कार्रवाई नहीं करने तथा दुकान के सीसीटीवी सिस्टम को अद्यतन नहीं रखने के कारण आबकारी उपनिरीक्षक पी. माधव राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में 25 जुलाई को जब्त 53 पेटी अवैध देशी एवं विदेशी शराब की जांच में होलोग्राम के आधार पर शराब का स्रोत बालोद जिले की अरकार देशी कम्पोजिट शराब दुकान पाया गया। जांच में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में थोक बिक्री सामने आने पर संबंधित वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक आशा राम शाक्य को भी निलंबित कर दिया गया है।

इसी प्रकरण में अरकार शराब दुकान की प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलोफर जैन के शिथिल नियंत्रण और कर्तव्य के प्रति लापरवाही को गंभीर मानते हुए आबकारी आयुक्त ने उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को भेज दी है।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, अधिक मूल्य पर बिक्री अथवा नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के जैविक उत्पादों की राष्ट्रीय मंच पर गूंज

■ **बायोफैच इंडिया-2026 में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के विष्णुभोग चावल और केवची के प्राकृतिक शहद ने बटोरी सराहना**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, महिला स्वसहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने तथा जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के प्रयास लगातार नई सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-बिहान के अंतर्गत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के महिला स्वसहायता समूहों एवं किसान उत्पादक संगठन द्वारा तैयार किए जा रहे जैविक उत्पादों ने देश के सबसे बड़े एवं प्रतिष्ठित जैविक उद्योग व्यापार मेला एवं सम्मेलन 'बायोफैच इंडिया-2026' में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

नई दिल्ली में आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला एवं सम्मेलन में जिले के प्रसिद्ध 'अरपा बिहान विष्णुभोग राइस' तथा 'केवची के जंगलों से संग्रहित प्राकृतिक शहद' का राष्ट्रीय स्टॉल में आकर्षक प्रदर्शन किया गया। इन उत्पादों ने देश-विदेश से पहुंचे खरीदारों, निर्यातकों, उद्योग विशेषज्ञों एवं जैविक उत्पादों से जुड़े प्रतिनिधियों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। यह उपलब्धि न केवल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले, बल्कि पूरे

छत्तीसगढ़ के जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाली साबित हुई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि, स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा महिला स्वसहायता समूहों की आर्थिक मजबूती को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी सोच का परिणाम है कि बिहान से जुड़ी महिलाएं आज केवल उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक आयोजनों में अपने उत्पादों का सफल प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ा रही हैं। इससे स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलने के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि तथा उन्हें स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।

बायोफैच इंडिया-2026 प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों तथा मोटे अनाज आधारित कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने वाला विश्वस्तरीय मंच है, जहां देश-विदेश के आयातक, निर्यातक, विपणन विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और व्यापारिक संस्थाएं एकत्रित होकर जैविक उत्पादों के व्यापार एवं निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करते हैं। ऐसे प्रतिष्ठित मंच पर छत्तीसगढ़ के उत्पादों की प्रभावी उपस्थिति राज्य के किसानों, महिला स्वसहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए नए व्यापारिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी।

जिला मिशन प्रबंधक श्री दुर्गाशंकर सोनी ने बताया कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में जैविक विष्णुभोग धान एवं प्राकृतिक शहद के साथ-साथ सूरन, कटहल तथा अन्य जैविक सब्जियों के उत्पादन को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इन उत्पादों की गुणवत्ता, प्राकृतिक उत्पादन पद्धति तथा विशिष्ट स्वाद के कारण राष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिला स्वसहायता समूह आर्थिक रूप से सशक्त होकर आत्मनिर्भर बनने के साथ लखपति दीदी अभियान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उत्पादों की भागीदारी से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और उनके लिए बेहतर विपणन के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।

बायोफैच इंडिया-2026 में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जैविक उत्पादों की प्रभावशाली उपस्थिति इसी दूरदर्शी सोच और ग्रामीण विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है।

कार्यरत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक पास करना होगा टीईटी

■ **नसुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, नौकरी और पदोन्नति पर पड़ सकता है असर**

रायपुर। कार्यरत शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को टीईटी परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। निर्धारित समय-सीमा तक टीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षकों की नौकरी और पदोन्नति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी और प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक की समय-सीमा निर्धारित की है।

पुनर्विचार याचिका (सिविल) डायरी क्रमांक 53434/2025 (STATE OF U.P. versus ANJUMAN ISHAAT-E-TALEEM TRUST & OTHERS) तथा सिविल अपील क्रमांक 1385/2025 में 29 मई 2026 को पारित आदेश के पैरा-34 में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संबंधित राज्य एवं सक्षम प्राधिकारी टीईटी परीक्षा नियमित रूप से आयोजित करें। अधिमानत: हर साल दो बार,

लगभग छह माह के अंतराल पर परीक्षाएं आयोजित की जाएं, ताकि पात्र शिक्षक वैधानिक आवश्यकता पूरी कर सकें।

फेडरेशन के अनुसार, 1 सितंबर 2025 के आदेश के पैरा-216 में उल्लेख है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से कम शेष है, वे सेवानिवृत्ति तिथि तक पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन पदोन्नति के विचार क्षेत्र से बाहर रहेंगे। पैरा-218 में दोहराया गया है कि टीईटी अर्हता न रखने वाले सेवारत शिक्षक पदोन्नति के लिए विचारणीय नहीं होंगे। निर्धारित समय-सीमा में टीईटी पास न करने पर नौकरी पर खतरा बना रहेगा।

फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत में टीईटी का आयोजन एनसीटीई के दिशा-निर्देशों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सीबीएसई सीटीईटी आयोजित करता है, जबकि छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापमं द्वारा सीजी टीईटी आयोजित की जाती है। एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं था। छत्तीसगढ़ में जुलाई 2011 के बाद परीक्षाएं हुईं, लेकिन भर्ती नियमों एवं नियुक्ति पत्रों में टीईटी का उल्लेख न होने के कारण लंबे समय से कार्यरत हजारों शिक्षकों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. वि./यां. संभाग नवा रायपुर छ.ग.

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक. 1935/NIT-17/2026-27/व.ले.लि. नवा रायपुर दिनांक 03/08/2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से निम्नालिखित मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

एनआईटी क्र निविदा क्र.	कार्य का नाम No of Calls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
17 T0063	PROVIDING AND FIXING ELECTRICAL INSTALLATION IN BARRICADING AND HUTMENT FOR CG STATE GOVT GUEST HOUSE AT PLOT NO 2D SECTOR 30 VASHI MUMBAI MAHARASTRA द्वितीय आमंत्रण	2.4

नोट :- निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 10/08/2026 अपरान्ह 5:30 बजे तक है।

निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

शर्तें:- 1) उपरोक्त कार्यो के आबंटन प्राप्त होने पर ही नियामानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. वि./यां. संभाग
नवा रायपुर छ.ग.

जी-262702572/3

ब्राह्मण वोट बैंक के लिए योगी और अखिलेश आमने-सामने

नीरज कुमार दुबे

अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी बनाम अखिलेश की सियासत अब सीधे जातीय समीकरणों के अखाड़े में उतर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां समाजवादी पार्टी के पीडीए की नई-नई राजनीतिक व्याख्याएं गढ़ते हुए कभी इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी तो कभी प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताते हैं, वहीं अब अखिलेश यादव ने उसी पीडी का नया अर्थ निकालकर भाजपा को उसी के अंदाज में जवाब दिया है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित है। यानी जिस नारे को भाजपा लगातार निशाने पर ले रही थी, उसे सपा प्रमुख ने ब्राह्मण राजनीति के नए दरवाजे में बदलने की कोशिश कर दी। दरअसल, समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध समाज सम्मेलन श्रद्धांजलि से ज्यादा राजनीतिक संदेश का मंच बन गया। अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र को समाजवादी आंदोलन का बड़ा चेहरा बताते हुए ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का संदेश दिया और साफ संकेत दिया कि 2027 की लड़ाई में सपा सिर्फ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ब्राह्मण मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश ने योगी सरकार पर कई मोर्चों से हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए विकास दुबे एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि जिस दिन गाड़ी पलटी थी, उस दिन गाड़ी नहीं, सरकार पलटने से बच गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि समय आने पर सैटेलाइट इमेज सामने आएगी, जिससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गड़बड़ी के मुद्दे को उठाते हुए भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हिंदू धर्म में दान की रसीद नहीं मांगी जाती, लेकिन अब रसीदों की राजनीति हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को भी उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ हथियार बनाया। हम आपको बता दें कि ब्राह्मणों को लेकर अखिलेश का यह नया दांव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह वर्ग लंबे समय तक सत्ता की धुरी रहा है। आजादी के बाद शुरुआती दशकों में ब्राह्मण मतदाता मुख्य रूप से कांग्रेस के साथ रहे। मंडल-कमंडल की राजनीति के दौर में उनका बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर चला गया और राम मंदिर आंदोलन ने इस रिश्ते को और मजबूत किया। हालांकि 2007 में मायावती ने ब्राह्मण-दलित सोशल इंजीनियरिंग के सहारे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर यह साबित कर दिया था कि ब्राह्मण वोट पूरी तरह किसी एक दल की स्थायी जागीर नहीं हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के उभार के बाद से ही यह वर्ग भाजपा के साथ रहा लेकिन तमाम कारणों के चलते ब्राह्मण भाजपा से नाराज बताये जा रहे हैं जिसके चलते अब एक बार फिर यही वर्ग सभी राजनीतिक दलों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी भी इस मुकाबले में पीछे नहीं है। मायावती पहले ही ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देने और उन्हें सम्मानजनक भागीदारी देने की रणनीति का ऐलान कर चुकी हैं। उनका दावा है कि ब्राह्मणों सहित सवर्ण समाज के हित सबसे सुरक्षित बसपा में हैं और 2007 जैसा समीकरण दोबारा बन सकता है। ऐसे में साफ है कि 2027 के चुनाव में ब्राह्मण वोटों के लिए भाजपा, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। उधर, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी इसी राजनीतिक तल्खी की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया।

बांकीपुर उपचुनाव क्यों, कैसे और किसके चलते हारी भाजपा ?

कमलेश पांडे

बांकीपुर उपचुनाव 2026 में भाजपा की हार अब हर किसी को नहीं पच रही है। इसलिए लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाजपा क्यों हारी? कैसे पराजित हुई? और किसके चलते यह राजनीतिक दुर्दिन देखना पड़ा? बिहार वासी जानना चाहते हैं! क्योंकि 9 माह पहले ही तो उन्होंने जदयू नीत एनडीए गठबंधन को अभूतपूर्व बहुमत दिया था! अटकलें हैं कि क्या जदयू नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई %सियासी बदतमीजी% के बाद भाजपा अआखिर ब अकेले नहीं चल पाएगी, क्योंकि टीम नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के हवा-हवाई रणनीतिकारों को असली राजनीतिक जमीन पर तगड़ी पटकनी दिला डाली है!

जानकारों की मानें तो चाहे चिराग पासवान हों, जीतनराम मांझी हों या उपेंद्र कुशवाहा हों, या मुंह फुलाए सवर्ण भाजपाई, सबकी खामोशी या राजनीतिक बकवास दोनों भाजपा पर भारी पड़ गई। वह हो गया, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी! इसलिए ज्वलंत प्रश्न उठता है कि क्या भाजपा केवल अपने सहयोगियों और सहयोगी दलों दोनों के भितरघात की वजह से हारी है? क्योंकि ऐसे मतदान केंद्र जहां सहयोगी दल परंपरागत रूप से मजबूत रहे हैं, फिर भी वहां भाजपा को असामान्य रूप से कम वोट मिले हैं। खुद पार्टी और गठबंधन के नेताओं द्वारा दबी जुबान में ये बातें कहीं जा रही हैं, ताकि उनका महत्व बढ़े।

लिहाजा, सुलगते सवाल उठने लगे कि आखिर बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री (छ्टू) बनने के बाद हुए पहले ही बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जिस प्रकार की तगड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंतरिक युगलबंदी के खिलाफ किसी अंदरूनी राजनीतिक साजिश का द्योतक तो नहीं है!

चर्चा तो यहां तक हो रही है कि आनन-फानन में जिस तरह से पार्टी उम्मीदवार बदला गया, उस साजिश के पीछे केंद्रीय मंत्री अमित शाह की टीम में उपजे अंतर्विरोधों और आरएसएस से जुड़े दिग्गजों की परोक्ष भूमिका तो कहीं नहीं है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अव्यवहारिक पैराशूट नियुक्ति के बाद से ही

अंदर ही अंदर खफा चल रहे थे और मौका मिलते ही उन्हें, उनकी ही जमीन पर असली जातीय और पार्टीगत दोनों राजनीतिक औकात दिखा दी!

ऐसा इसलिए कि जो पार्टी दुर्लभ से दुर्लभतम चुनाव जीत जाती है, वह आखिर अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा छोड़ी हुई इकलौती सीट, जिस पर गत 30 वर्षों से %पिता-पुत्र% का कब्जा रहा हो, वह अचानक हार जाए। खुद पटना के पीढ़ी दर पीढ़ी वाले भाजपा समर्थक संभ्रांत लोग भी अचंभित रह गए हैं कि ये क्या हो गया? क्या %लालू की नीति% दबे पांव वेश बदलकर उनके पुत्र तेज प्रताप यादव के शह पर पटना में आ गई? क्या सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं को अपेक्षित स्तर पर सक्रिय नहीं किया गया? क्या स्थानीय स्तर पर असंतोष या गुटबाजी को शांत नहीं किया गया? क्या उम्मीदवार चयन को लेकर नाराज़गी नहीं भांपी जा सकी? क्या विपक्ष के प्रभावी ध्रुवीकरण का अंदाजा भाजपा रणनीतिकार नहीं लगा पाए? क्या स्थानीय मुद्दे और सत्ता-विरोधी भावना प्रबल रही और मतदान प्रबंधन यानी बूथ मैनेजमेंट में कमी बरती गई?

उनका सीधा सवाल यह भी है कि आखिर पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ सी पी ठाकुर (सांसद विवेक ठाकुर के पिता), राज्य सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव और अशोक चौधरी के मोहल्लों से जुड़े मतदान केंद्रों पर भी भाजपा प्रत्याशी कैसे पिछड़े और प्रशांत किशोर वहां भी बढ़त बनाए रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बूथ की भी यही स्थिति रही। आखिर यह सब सियासी प्रपंच कैसे और क्यों संभव हुआ? क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बदलने के लिए इतना बड़ा आत्मघाती षड्यंत्र सवर्णों के नेताओं ने अपने ही खिलाफ रच दिया? क्या किसी ने इस हेतु नई दिल्ली और नागपुर से इशारा भी किया था? बात पचने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है।

सवाल है कि क्या आरएसएस और भाजपा के जमीनी तालमेल की कमी ही भाजपा के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण है। क्या भाजपा और उसके वैचारिक-संगठनात्मक नेटवर्क के बीच स्थानीय स्तर पर समन्वय में कमी रही? क्या उम्मीदवार चयन या स्थानीय असंतोष का प्रभाव पड़ा? क्या विपक्ष ने नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बनाए? क्या कम मतदान का असर भाजपा के पारंपरिक मतदाता आधार पर पड़ा?

सवाल यह भी है कि क्या जदयू के पूर्वमुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने द्वारा ही बनवाए हुए भाजपाई मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सियासी बदला ले लिया गया है? या फिर पूर्वमुख्यमंत्री व कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, और पूर्व कानून मंत्री व सांसद रविशंकर प्रसाद के अलावा ऋ्षराज सिन्हा और संजय मयूख जैसे दिग्गज कायस्थ नेताओं ने निजी कारणों से भितरघात किया/कराया है? क्या लोजपा रामविलास के नेता व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी भाजपा को दिली सहयोग नहीं मिला? क्या उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी और जीतनराम मांझी और नागमणि जैसों के विषैले बोलों की कीमत भाजपा ने चुकाई है।

वहीं, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यूजीसी बिल विवाद, ओबीसी/दलितों को ज्यादा कानूनी तरजीह दिए जाने, हिंदुत्व को गफलत में रखने और राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण के अलावा भरत तिवारी एनकाउंटर प्रकरण आदि ने सवर्णों के बीच भाजपा की राजनीतिक साख को गहरी चोट पहुंचाई है। आलम यह बताया गया है कि ओबीसी/दलित वोट बैंक भाजपा के साथ पूरी तरह से नहीं जुटा पाया है,जबकि सवर्णों का सजग तबका अपने बच्चों के भविष्य के खातिर भाजपा से दूर चला जा रहा है, या विकल्प ढूंढ रहा है। क्या जन सुराज पार्टी में वह विकल्प दिखाई दे चुकी है? क्या सवर्णों ने बीजेपी को धोखा दिया या ओबीसी और दलितों ने या फिर तीनों वर्गों के समृद्ध तबके ने?

देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शोषित, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज की राजनीति को धार देने की कोशिश तो की थी, पर कामयाबी नहीं मिली। लिहाजा, इस चुनाव में उन्होंने न केवल मुद्दे बदलते, बल्कि मोदी-शाह-सम्राट पर सीधे निशाना साधकर ही सफलता के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, बिहार में भाजपा के लिए जन सुराज पार्टी अब एक वास्तविक चुनावी चुनौती बन चुकी है, जिसको राष्ट्रीय विस्तार पाते देर नहीं लगेगी। क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति यही चुगली कर रही है।

बांकीपुर उपचुनाव को प्रशांत किशोर ने व्यक्तिगत अभियान में बदल दिया था। उनकी पार्टी जन सुराज ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और प्रशांत किशोर ने स्वयं मैदान में उतरकर इसे हाई-प्रोफाइल मुकाबला बना दिया। इससे

विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और भाजपा विरोधी मत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राजद प्रत्याशी की ओर न जाकर अपेक्षाकृत अधिक एक दिशा में गए जिससे जनसुराज को विजयश्री मिली और भाजपा को नुकसान हुआ।

जहां तक एंटी-इनकंबेंसी की बात है तो बांकीपुर लंबे समय से भाजपा का गढ़ था, जहां लगातार एक ही दल के प्रतिनिधित्व से कुछ मतदाताओं में बदलाव की इच्छा पैदा हो गई प्रतीत होती है। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी हावी रहे। विपक्ष ने पूर्व घोषित उम्मीदवार के अकस्मात बदलाव, बूथ प्रबंधन, स्थानीय संगठन और मतदान प्रतिशत जैसे कारक को भी उछाला, जो निर्णायक भूमिका निभाए। जबकि शहरी मतदाता का बदलता रुझान भाजपा पर भारी पड़ गया। शिक्षित और युवा मतदाताओं ने परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया, क्योंकि यूजीसी बिल का सर्वाधिक प्रभाव उन्हीं पर पड़ता। इसलिए इन बातों का प्रभाव परिणाम पर पड़ा है।

पहले सीजेपी द्वारा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे स्वीकार करवाना और अब जेएसपी के प्रशांत किशोर द्वारा भाजपा का मजबूत गढ़ तोड़ दिया जाना बहुत कुछ संकेत दे रहा है, जो यह साबित करता है कि उनकी पार्टी केवल वैचारिक मंच नहीं, बल्कि चुनाव जीतने की क्षमता भी रखती है। वहीं, अब बिहार और देश की राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ चुकी है, क्योंकि जन सुराज पार्टी अब एक स्थायी ताकत बन चुकी है। भविष्य के चुनावों में मुकाबला केवल एनडीए बनाम महागठबंधन तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि तीसरा गुट भी बनेगा।

पुराण दिग्दर्शन ....

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

तथापि जल के अमुक भाग में अमुक गुण की विशिष्टता से अथवा अमुक 2 देश के तट-सान्निध्य से वर्तमान गवेषकों ने भी उस एकत्व-संख्यावच्छिन्न समुद्र के सात विशिष्ट भाग माने हैं अत: वे भी सात समुद्र बलताते हैं। यदि हम पुराणवर्णात दही दूध के समुद्रों के साथ वर्तमान समुद्रों के नामों की तुलना करें तो सहसा यह स्पष्ट हो जायेगा कि अब भी उन 2 समुद्रों के नाम प्राय: पौराणिक नाभों के समान ही प्रसिद्ध हैं यथा-इक्षुरस समुद्र (सीमोर स्द्धद्गशह स्द्गड्डु) सुरा समुद्र (अटलांटिक Atlantic Ocean) सर्पि: समुद्र (हड़सन Hudson) दधिमण्ड समुद्र (अण्टरेक्टिक Antarectic) क्षीरसागर (ह्वाइट White Ocean) स्वादक (रूमसागर Mediterranean Sea) लवण-समुद्र Indian Ocean)।

पार्थिव-सुमेरु

यदि हम पुराणोक्त लक्षण के अनुसार पार्थिव-सुमेरु का अन्वेषण करना चाहें तो एशिया और यूरोप की सीमा को विभक्त करने वाला यूराल नामक पहाड़ ही हो सकता है। क्योंकि पुराणों में सुमेरु को भूमण्डल का मध्यस्थ पर्वत माना है तदनुसार पार्थिव-मेह भी हमारी इस पृथ्वी के ठीक मध्य में होने वाला ही कोई पहाड़ होना चाहिए। सो यदि पूराल पर्वत की मध्य चोटी पर से पृथ्वी के गोले परं एक रेखा- जो गोले को ठीक दो भागों में बाँटने वाली हो- यूपूर ल से पूर्व की तरफ फारमूसा द्वीप (सिधाई और हाङ्गकांग के बीच में) तथा शाकद्वीप- वर्तमान आस्ट्रेलिया के पूर्व किनारे को काटती हुई और यूराल से पश्चिम की तरफ सैनिक (हालेण्ड) से ऊपर इङ्गलैंड में लन्दन की ओर होती हुई दक्षिणी अमेरिका को काटती हुई खींची जावे तो इस रेखा पर पृथ्वी के सूखे भाग की लम्बाई जितनी पूर्व रेखा पर होगी ठीक उतनी ही पश्चिमी रेखा पर भी होगी। **क्रमशः...**

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर

रवींद्रनाथ टैगोर की आज पुण्यतिथि है। 07 अगस्त 1941 को कोलकाता में उनका निधन हो गया। हमारे देश का राष्ट्रगान तो उनका लिखा है ही साथ ही बांग्लादेश का एंथेम भी उन्हीं का लिखा है। साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रगान के सुरों में उनका असर है। वो शायद पहले ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने ये खास उपलब्धि हासिल की हुई है।

टैगोर के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की तो आज भी धाक है। कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, निबंधकार, नाटककार और चित्रकार सभी रहे रवींद्रनाथ टैगोर वाकई अपनी प्रतिभा में बेजोड़ थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा भव्य और आकर्षक कि किसी को भी आकर्षित कर ले।

रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके

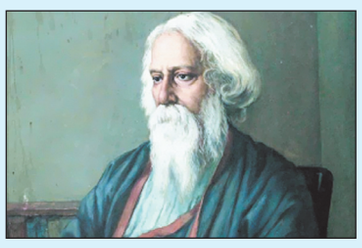

पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक जाने-माने समाज-सुधारक थे। टैगोर की पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल से हुई थी। लंदन में उन्होंने कानून की पढ़ाई की पर बिना डिग्री लिए ही वापस चले आये।

रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है। बचपन में ही उनका रुझान कविता और कहानी लिखने की ओर हो चुका था। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी। 1877 में वह 16 साल के थे जब उनकी पहली लघुकथा प्रकाशित हुई थी। गुरुदेव को उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।

टैगोर को नाइटहुड की उपाधि भी मिली हुई थी। जिसे टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919) के बाद अपनी लौटा दिया था। 1921 में उन्होंने शांति निकेतन की नींव रखी थी। जिसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। टैगोर को बाद में गीतांजलि काव्य संकलन के लिए नोबल पुरस्कार हासिल हुआ। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में बांग्ला भाषा विभाग में प्राध्यापक डॉ. प्रकाश कुमार मैती के अनुसार रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाएं बांग्ला साहित्य में अनोखी हैं। उन्होंने एक दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। इन रचनाओं में चोखेर बाली घरे बाइरे गोरा आदि शामिल हैं। उनके उपन्यासों में मध्यम वर्गीय समाज विशेष रूप से उभर कर सामने आया है।

स्वामी विवेकानंद के बाद रवीन्द्रनाथ टैगोर दूसरे व्यक्ति थे, जिन्होंने विश्व धर्म संसद को दो बार संबोधित किया। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। उनका शांत अप्रतिम व्यक्तित्व भारतवासियों के लिए सदैव ही सम्माननीय रहा है। गुरुदेव का लिखा एकला चालो रे गाना गांधीजी के जीवन का आदर्श बन गया।

गुरुदेव का संदेश था शिक्षा से ही देश स्वाधीन होगा संग्राम से नहीं। कहना न होगा कि आज भी यह संदेश कितना प्रासंगिक है।

टैगोर की रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनीं। भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला उन्हीं की रचनाएं हैं।

क्या मुनीर पाक में तख्तापलट का मन बना चुके हैं?

मनिंदर सिंह गिल

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हालिया बयानों ने पाकिस्तान की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। मोहसिन नकवी, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के करीबी माने जाते हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें इंटीरियर मिनिस्ट्री मिल गई है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम जर्जर हो गया है और पाकिस्तान के लोगों को सुविधाएं देने तथा युवाओं की आकांक्षाएं पूरी करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बहुत मेहनत से काम करते हैं लेकिन अगर वह 18-18 घंटे भी काम करें तो भी पाकिस्तान का कुछ नहीं संवार सकते। इस बयान से उन्होंने पाकिस्तान में प्रशासनिक फेरबदल की ओर इशारा किया और यह भी कहा कि पाकिस्तान के 4 सूबों को बांटकर और प्रशासनिक ब्लॉक, जिन्हें सूबे या कुछ और नाम दें, बनाने की जरूरत है, ताकि ताकत निचले स्तर तक लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने अपने बयानों में पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमैंट यानी सेना की बड़ी भूमिका का भी जिक्र किया।

इस कॉन्फ्रैंस के बाद जब पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता डी.जी.आई.एस.पी.आर. अहमद शरीफ चौधरी से नकवी के इन बयानों के बारे में सवाल किए गए, तो उन्होंने साधारण रूप से तो कहा कि वे राजनीतिक बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन फिर उन्होंने नकवी द्वारा जताए गए सभी विचारों का समर्थन किया और राजनीतिक नेतृत्व की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा को तब तक यकीनी नहीं बनाया जा सकता, जब तक प्रशासन अपना कार्यभार अच्छी तरह नहीं संभालता, जहां से यह स्पष्ट इशारा मिल गया कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमैंट, जिसके प्रमुख आज के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वह अब अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं और यह भी हो सकता है कि वह मिलिट्री के साथ-साथ राजनीतिक नेतृत्व भी खुद संभाल लें, जिसे एक

तरह का तख्तापलट ही माना जा सकता है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमैंट के साथ जुड़े विभिन्न मीडिया संस्थान और अन्य प्रवक्ता भी इस बयान के बाद तुरंत सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ अपने-अपने विचार देने शुरू कर दिए हैं, जहां से लगता है कि आसिम मुनीर साहब अब रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक का फासला तय करने का मन बना चुके हैं।

पाकिस्तान में यह पहली बार नहीं हो रहा कि किसी सैन्य जनरल ने सत्ता अपने हाथों में ली हो, लेकिन आज जो क्षेत्र के हालात बने हुए हैं उनके मद्देनजर आसिम मुनीर का इस तरह सत्ता हथियाने की ओर बढऩा बहुत मायने रखता है। एक तरफ अमरीका ईरान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान अमरीका को फायदे पहुंचाकर अपना रास्ता साफ करना चाहता है। जिससे साफ है कि बहती गंगा में अब आसिम मुनीर भी हाथ धोना चाहते हैं, हालांकि पाकिस्तान की मिलिट्री पहले ही राजनीति को कंट्रोल करती है और अपनी मर्जी की पार्टियों को जिताना-हराना और सरकारें बनवाना एक आम बात है लेकिन अब प्रशासनिक फेरबदल के नाम पर आसिम मुनीर क्या करना चाहते हैं, यह भविष्य में देखने वाली बात होगी।

इससे पहले सैन्य तानाशाहों जनरल अयूब खान, जनरल जिया-उल-हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की सदर बनने की ख्वाहिश तो पूरी हुई, पर उसके बाद वे सत्ता पर काबिज नहीं रह सके। क्योंकि फील्ड मार्शल होने के नाते आज सेना की सारी ताकत आसिम मुनीर के हाथों में है लेकिन अगर वह राष्ट्रपति बन जाते हैं और सेना का कार्यभार किसी अन्य जनरल को सौंप देते हैं, तो क्या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमैंट उनकी सदारत को ताकतवर रहने देगी या फिर वह अपने नए चीफ के आदेशों की ओर देखेगी? क्या आसिम मुनीर आर्मी चीफ और सदर दोनों ही पदों पर बने रह सकते हैं? अगर बात सूबों के पुनर्गठन की करें तो भारत और पाकिस्तान एक ही समय पर आजाद हुए। भारत में भाषा के आधार पर सूबे बनाने का पहले बहुत विरोध था लेकिन फिर सरकार ने यह अहसास किया कि भाषा के आधार पर सूबे बनाने से देश और मजबूत होगा, इसलिए भाषा के आधार पर कई सूबे बनाए गए और सूबों का पुनर्गठन समय-समय पर होता रहा। लेकिन पाकिस्तान में 1947 के समय 3 सूबे थे, चौथे बलूचिस्तान को सैन्य ताकत के जरिए धक्के से हथिया लिया गया और देश का चौथा सूबा बनाया गया। बीते 75 सालों में सूबों का किसी भी तरह का पुनर्गठन नहीं हुआ।

विभिन्न समय पर यह मांग उठती रही कि पाकिस्तानी पंजाब के दक्षिणी हिस्से, जिसे साऊथ पंजाब कहा जाता है, बहावलपुर का इलाका, जो कि विकास के पक्ष से बहुत पिछड़ा हुआ है, को उत्तरी पंजाब से अलग करके एक नया सूबा बना दिया जाए या जो सराइकी इलाका है उसे अलग सूबा बना दिया जाए। लेकिन क्या पंजाब की डोमिनैंट कम्युनिटी, जो कि पाकिस्तानी आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा है और पाकिस्तान में हर तरफ छाई हुई है, अपने राजनीतिक रुतबे में कमी स्वीकार करेगी?

इसी तरह सिंध में, जहां सिंधु देश की मांग बार-बार उठती रही है, क्या सिंधी लोग यह बर्दाश्त करेंगे कि उनके प्रमुख शहर कराची को सिंध से अलग कर दिया जाए? यह किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन होगी? इसका खाका अभी जनता के सामने नहीं आया है। अगर बात बलूचिस्तान की करें तो वह बिल्कुल ही अलग है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ अलगाव का संघर्ष लगातार चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग, जो नस्ली रूप में पख्तून हैं, वे अपनी समानता अफगानिस्तान की पख्तून आबादी के साथ देखते हैं। अत: पाकिस्तान को क्या सिर्फ प्रशासनिक आधार पर ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिस तरह अंग्रेजों के जमाने में किया जाता था या पाक सरकार अपने देश के भाषाई, सांस्कृतिक और विकास के मानकों को ध्यान में रखते हुए अपने मुल्क को ऑर्गेनाइज करेगी? जो भी होने जा रहा है, इससे पाकिस्तान में एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल की संभावनाओं से लगता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले मकबूजा कश्मीर में संवैधानिक बदलाव कराने के लिए एक बड़ी तंजीम चल रही है, जिस पर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने बहुत अत्याचार किया है, गोली चलने से कई लोगों की मौत की खबर भी आ रही है।

क्या आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रम्प से पाकिस्तान की मुकम्मल सत्ता हथियाने के लिए हरी झंडी ले चुके हैं? क्या वह ईरान पर हुए अमरीकी हमले से बने राजनीतिक हालात को अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं? यह अब समय ही बताएगा लेकिन एक बात जरूर है कि आसिम मुनीर के हाथों में बेतहाशा सत्ता का आना इमरान खान के समर्थकों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। खैर, पाकिस्तान में उथल-पुथल दक्षिण एशिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं, क्योंकि दक्षिण एशिया के मुल्कों नेपाल, बंगलादेश और श्रीलंका में पहले ही राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है और भारत में भी जेन-की आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर पकड़ को कमजोर किया है। इस दौरान अगर पाकिस्तान में भी राजनीतिक उथल-पुथल होती है तो इसका असर पूरे साऊथ एशिया के क्षेत्र में पहुंच जाएगा।

आज का इतिहास

1606 शेक्सपीयर के नाटक मैक्बेथ का पहली बार मंचन किंग जेम्स प्रथम के लिए किया गया।
1880 उचित वक्ता पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था।
1905 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया।
1941 नोबेल पुरस्कार विजेता गुरूदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर का निधन।
1944 पहले कैलकुलेटर के नाम पर 51 फीट लंबी, 8 फीट ऊंची और पांच टन वजन की एक विशाल मशीन का निर्माण।
1947 मुंबई नगर निगम को बिजली और परिवहन व्यवस्था औपचारिक रूप से हस्तांतरित हुई।
1957 अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया।
1960 अफ्रीका महाद्वीप के देश आइवरी कोस्ट को फ्रांस के अधिकार से आजादी मिली।
1972 युगांडा के नेता इदी अमीन ने एशियाई मूल के लोगों को 90 दिन के भीतर देश छोड़कर चले जाने का आदेश दिया।
1985 गीत सेठी ने विश्व अमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती।
1990 अमेरिका ने सऊदी अरब में सेना तैनात कर ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू किया।
1996 अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा 13 हज़ार वर्ष पूर्व पृथ्वी पर गिरे उल्का पिंड के अवशेषों से मंगल ग्रह पर एक कोशिका वाले जीवों के होने की संभावना का पता चला।
1998 केन्या एवं तंजानिया की राजधानियों में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी हमले में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु।
1999 पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ ने एक बार फिर भारत से वार्ता की पेशकश की।
2000 रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन द्वारा एक क़ानून पर हस्ताक्षर कर अपनी शक्ति का विस्तार।
2003 बगदाद में जार्डन दूतावास के बाहर हुए कार बम विस्फोट में 12 लोगों की मृत्यु।
2005 इस्त्रायल के वित्तमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया।
2008 सार्वजनिक क्षेत्र के देना बैंक ने अपनी प्रथान ब्याज दरें 0.75% बढ़ाकर 14.25% करने की घोषणा की। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्पोरेशन बैंक ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 0.50% बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की।
2018 देश में द्रमुक राजनीति का सशक्त चेहरा रहे एम करूणानिधि का निधन।

कैसे अकेले दम पर राजनीति का रुख बदलने में लगे ये लोन वॉरियर्स

अभिनय आकाश

बिहार में जिस सीट पर प्रशांत किशोर की जीत हुई है, यह वो सीट है जिसको लेकर दबी जुबान में अक्सर बीजेपी वाले कहते थे कि यहां कुत्ता बिल्ली भी चुनाव लड़ा देंगे तो वो जीत जाएगा। और वो गलत नहीं कहते थे। हां, क्योंकि यह बांकीपुर था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अपना घर जिस सीट से वह एक दो बार नहीं लगातार पांच बार जीते थे और यहीं से जीतकर वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। 15 साल से यहां कमल का बटन लगातार दब रहा था और नतीजा पहले से ही लिखा था और ताना उस आदमी को मारा जा रहा था जिसने 243 सीटों पर लड़कर शून्य जीता था। जिसको लेकर बिहार में मीम भी वायरल हुए थे। प्रशांत तब खुलकर कहते थे कि मैं मरा नहीं हूं अभी अभी जिंदा हूं। अभी मैं मरा नहीं हूं। अभी नहीं मरा हूं। जब मर जाऊंगा तो फिर लिखना अभी मरा नहीं हूं। अब इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है। पटना के गिनती वाले हॉल में राउंड द राउंड वही मजाक भारी पड़ता गया जैसे पंचायत में आपको याद होगा। विधायक जी हार गए थे और सामने वाली पार्टी जीत गई थी। प्रशांत किशोर के समर्थक भी वैसे ही डांस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज सावन के सोमवार के दिन बाबा का आशीर्वाद मिल गया। पीके ने केवल एक सीट का चुनाव नहीं जीता है। बांकीपुर बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ी सी और 1995 से ये सीट बीजेपी के पास रही थी। पहले पटना वेस्ट और फिर 2008 के परिसीमन के बाद बांकीपुर से पांच बार नितिन और उससे पहले उनके पिता नवीन प्रसाद सिन्हा तीन बार इस सीट से विधायक रहे। प्रशांत किशोर ने इस सिलसिले को तोड़ दिया है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत ने देश की राजनीति में एक नए ट्रेंड को रेखांकित किया है। भले ही प्रशांत किशोर, चंद्रशेखर आजाद (आजाद समाज पार्टी), असदुद्दीन ओवैसी और जयराम महतो जैसे नेता अपनी-अपनी पार्टियों के अकेले सांसद या विधायक हों, लेकिन संसद और विधानसभाओं से लेकर जनता के बीच इनकी आवाज और राजनीतिक प्रभाव किसी बड़ी पार्टी से कम नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे एकल राजनीतिक चेहरे अपने मुद्दों, सोशल मीडिया पकड़ और बेबाक नेतृत्व के दम पर पारंपरिक बहुदलीय व्यवस्था के बीच अपनी एक मजबूत और असरदार पहचान बना रहे हैं।

पटना का दिल है बांकीपुर गांधी मैदान से

सटा इलाका पढ़े लिखे लोग दुकानदार नौकरी पेशा वो इलाका जहां शाम को चाय की दुकान पर राजनीति उबलती है और वोट हमेशा एक तरफ गिरता है। 2010 से यहां एक ही चेहरा जीतता है नितिन नवीन सफेद कुर्ता माथे तिलक पटना की गलियों में जाना पहचाना आदमी और उससे पहले उनके पिताजी यही जीतते थे यानी यह सीट पार्टी के लिए सीट थोड़ी थी घर की बैठक थी कि यहां यहां तो हम जीते यहां कौन सा टेंशन है? फिर हुआ यह कि नितिन नवीन की किस्मत अचानक से उछाल मार दी गई। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। राज्यसभा चले गए और फिर पीछे ये सीट खाली। भाजपा तो ये मान के बैठी थी कि भाई घर है हमारा। 15 साल का रिकॉर्ड है। जीत पक्की है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर के विरुद्ध एक मंडल कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के रणनीतिकार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति को अर्थ देने की कोशिश की- चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर...! वर्ष 2025 विधानसभा के चुनावी जंग में बुरी तरह पिटे प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर किसी कोरामीन से कम नहीं। बीजेपी की रणनीति थी कि एक साधारण कार्यकर्ता से प्रशांत किशोर को पराजित कर उनकी आखिरी उम्मीद को ध्वस्त किया जाए।

चंद्रशेखर आज़ाद : किशोर से पहले, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के टिकट पर उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चुने गए थे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 1.51 लाख वोटों से हराया था। 38 वर्षीय आज़ाद, जो दलितों के एक प्रमुख नेता हैं, ने 2022 में गोरखपुर अर्बन सीट से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपना पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन वे हार गए और उन्हें सिर्फ़ 3% वोट मिले। सांसद चुने जाने के बाद, आज़ाद संसद के अंदर और बाहर दलितों और मुसलमानों की एक बड़ी आवाज़ बनकर उभरे हैं। उन्हें लोकसभा में अलग-अलग मुद्दों पर बहस में हिस्सा लेने का समय मिलता है, साथ ही संसद के बाहर अपने आंदोलन के दौरान उन्हें सांसद का प्रोटोकॉल भी मिलता है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव तीसरे स्थान पर रहे। सोमवार को घोषित नतीजों में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हराया, जबकि दामोदर को 22,527 वोट मिले।

जयराम महतो : जयराम महतो, जिन्हें टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड विधानसभा में अपनी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के अकेले विधायक हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव गिरिडीह से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और उन्हें 3.47 लाख वोट मिले थे। इसके बाद, नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने जेएलकेएम को मान्यता दी, जिसमें वे डुर्मी सीट से चुने गए। उन्होंने बेरमो से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां वे दूसरे स्थान पर रहे। 31 साल के महतो ओबीसी कुडमी समुदाय के उभरते हुए नेता हैं और झारखंड के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। इन वीडियो में वे राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक नेताओं द्वारा जमा की गई संपत्ति, लोगों की गरीबी और इस बात पर बात करते हैं कि कैसे झारखंड में बाहरी लोगों को सरकारी नौकरियां मिलती हैं। अपने चुनावी नामांकन हलफनामे में उन्होंने यू-ट्यूब को अपनी आय का स्रोत बताया था। महतो, आज़ाद और किशोर में एक आम बात यह है कि वे अपनी-अपनी पार्टियों के युवा संस्थापक हैं और उन्होंने बदलाव और न्याय तथा नई राजनीति के अपने एजेंडे से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई है।

असदुद्दीन ओवैसी : एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से पांच बार सांसद रहे 57 वर्षीय असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में अपनी पार्टी के अकेले सदस्य हैं। देश में मुसलमानों की एक अहम आवाज़ के तौर पर उभरने के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। वे संसद और दूसरे सार्वजनिक मंचों पर बड़े राष्ट्रीय मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं, जिनमें मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। हालांकि एआईएमआईएम एक पुरानी पार्टी है, लेकिन ओवैसी ने इसके विस्तार की अगुवाई की है। अब तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पार्टी के कई विधायक और पार्षद हैं।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना महत्वपूर्ण पहल

ज्योति भास्कर

हाल ही में राज्यसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतर अदालतों में लंबित मामलों का जो आंकड़ा पेश किया, उससे देश की न्याय व्यवस्था पर बोझ का पता तो चलता ही है, यह भी स्पष्ट होता है कि देश की आम जनता को समय पर न्याय के बजाय तारीख-दर-तारीख ही क्यों मिलती रहती है। उनके मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय में अभी 96,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से 10,000 से ज्यादा मामले 10 साल से अधिक समय से विचाराधीन हैं, जबकि 558 मामले 20 साल से ज्यादा समय से और 26 मामले तीन दशक से अधिक समय से अनसुलझे हैं।

नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, देश की सभी अदालतों में 5.64 करोड़ से ज्यादा मामले अटके हुए हैं। उच्च न्यायालयों में भी 80,660 केस 30 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। ये आंकड़े महज न्यायिक व्यवस्था की सुस्ती की ही कहानी नहीं कहते, बल्कि उन करोड़ों लोगों की बेबसी की दास्तां भी बयान करते हैं, जो विचाराधीन कैदी के रूप में अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष जेल की सलाखों के पीछे गंवा देते हैं। अपनी बेगुनाही साबित करने में लोगों की जीवनभर की कमाई वकीलों की फीस और अदालतों के चक्कर काटने में खर्च हो जाती है।

आम तौर पर अदालतों में लंबित पड़े मामलों की सुनवाई तथा न्याय में देरी के लिए पर्याप्त संख्या में जजों, कर्मचारियों एवं आधारभूत संरचना की कमी का उल्लेख किया जाता है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2011 से अब तक अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और न्याय व्यवस्था में तकनीक को शामिल करने

पर 9,800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है।

अक्सर देखा जाता है कि जांच एजेंसियां समय पर और सही तरीके से साक्ष्य जुटाने में विफल रहती हैं, तो कभी जजों की कमी के कारण सुनवाई टल जाती है। देश के उच्च न्यायालयों में 1,122 स्वीकृत पदों के मुकाबले 341 जजों के पद खाली हैं। निचली अदालतों में 30,868 स्वीकृत पदों के मुकाबले 7,311 पद रिक्त पड़े हैं।

कॉलेजियम सिस्टम की वजह से हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए तय समय-सीमा पर नामों की सिफारिश नहीं करने से भी जजों की नियुक्तियां अटकी रहती हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने संबंधी विधेयक का लोकसभा में पारित होना एक महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन, जब तक उच्च व अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पद समयबद्ध तरीके से नहीं भरे जाते, न्यायिक आधारभूत ढांचे को मजबूत नहीं किया जाता और सरकार सहित सभी पक्ष अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने का प्रयास नहीं करते, तब तक न्याय में देरी का संकट शायद ही दूर हो सके।

उत्तरप्रदेश की राजनीति: एक थीं मायावती! वो कहां गुम हो गईं?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

एक थी मायावती। कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका नाम ही काफी था। उनके भाषणों में आक्रामकता थी, नारों में चुनौती थी और राजनीतिक फैसलों में ऐसा आत्मविश्वास था कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कांशीराम के साथ बहुजन आंदोलन से निकली मायावती ने राजनीति की उस सीढ़ी को पार किया, जिस पर चढ़ना कभी असंभव माना जाता था।

वह चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर यह साबित किया कि दलित राजनीति केवल विरोध की राजनीति नहीं, सत्ता हासिल करने की भी राजनीति हो सकती है। लेकिन आज वही मायावती राष्ट्रीय राजनीति में लगभग हाशिये पर दिखाई देती हैं।

मायावती के राजनीतिक पतन की चर्चा में एक महत्वपूर्ण मोड़ 2016 की नोटबंदी के बाद का दौर भी है। नोटबंदी पर मायावती ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया था, लेकिन इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष जिस तरह मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होता गया, मायावती उस मोर्चे की स्थायी साझेदार नहीं बनीं। यही वह दौर था जब उनकी राष्ट्रीय राजनीति और ज्यादा अलग-थलग दिखाई देने लगी। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि केवल नोटबंदी ने मायावती को हाशिये पर पहुंचाया।

उनके राजनीतिक पतन के पीछे संगठन की कमजोरी, सामाजिक आधार में बदलाव, नए दलित नेतृत्व का उभार और भाजपा तथा सपा की बदली हुई रणनीतियां भी जिम्मेदार रहीं। लेकिन नोटबंदी के बाद का दौर जरूर ऐसा रहा, जब राष्ट्रीय राजनीति में उनकी दृश्यता और प्रभाव तेजी से घटता दिखाई दिया।

यही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पहेली है। वह विपक्ष के पक्ष में भी पूरी तरह नहीं रहतीं और सत्ता पक्ष के साथ भी स्थायी रूप से नहीं जातीं। वह अक्सर विपक्ष के खिलाफ ही बोलती हैं, लेकिन सत्ता की साझा राजनीति का हिस्सा बनने से भी बचती हैं। यही कारण है कि उन्हें विपक्षी नेता कहना भी आसान नहीं है। वह पारंपरिक अर्थों में सत्तापक्ष की सहयोगी भी नहीं हैं और विपक्षी गठबंधन की नियमित सहभागी भी नहीं। उनकी राजनीति एक तरह की स्वतंत्र राजनीतिक धुरी बन गई है- लेकिन समस्या यह है कि वह धुरी अब उतनी मजबूत नहीं रही, जितनी कभी हुआ करती थी।

राष्ट्रीय राजनीति में इसका सीधा असर पड़ा। आज स्थिति यह है कि सत्तापक्ष भी मायावती को राष्ट्रीय स्तर पर उतनी गंभीर चुनौती नहीं मानता और मुख्य विपक्ष भी उन्हें अपनी रणनीति का अनिवार्य हिस्सा नहीं मानता। उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट प्रतिशत चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है, लेकिन दिल्ली की सत्ता की लड़ाई में मायावती की भूमिका पहले जैसी निर्णायक नहीं दिखाई देती।

यह शायद किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए सबसे कठिन स्थिति होती है- आपके पास अपना आधार हो, आपकी अपनी पार्टी हो, आपका अपना वोट बैंक हो, लेकिन देश की बड़ी राजनीतिक लड़ाई में बाकी दल आपको निर्णायक खिलाड़ी न मानें।

यही वह बिंदु है जहां एक थी मायावती का सवाल और गहरा हो जाता है। कभी भाजपा और सपा दोनों को मायावती की जरूरत पड़ती थी। कभी वह किसी गठबंधन को बहुमत तक पहुंचाने वाली ताकत थीं, तो कभी उनका विरोध किसी राजनीतिक दल के लिए बड़ा मुद्दा बन जाता था। आज स्थिति उलट गई है। भाजपा के पास अपना विस्तृत सामाजिक गठबंधन है, सपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई राजनीतिक जमीन बनाई है और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता की कोशिश करती है। इन बड़े राजनीतिक खेमों के बीच बसपा का स्वतंत्र रास्ता अब पहले जितना प्रभावशाली दिखाई नहीं देता।

इसका अर्थ यह नहीं कि मायावती की राजनीति समाप्त हो गई। बल्कि असली सवाल यह है कि क्या उन्होंने खुद को उस राजनीतिक स्थिति में पहुंचा दिया है, जहां दूसरे दलों को उनकी जरूरत महसूस नहीं होती?

राजनीति में अलग रहना तभी ताकत बनता है जब आपके पास इतना मजबूत जनाधार हो कि हर पक्ष आपको साथ लेने को मजबूर हो। अगर वही जनाधार लगातार कमजोर हो जाए, तो स्वतंत्र राजनीति धीरे-धीरे अलगाव में बदल सकती है। मायावती के सामने आज शायद यही सबसे बड़ा संकट है।

कभी उनकी राजनीति का आधार था- बहुजन बनाम सत्ता का सामाजिक ढांचा। फिर उन्होंने उसी राजनीति को बदलकर सर्वजन का प्रयोग किया। 2007 में दलित-ब्राह्मण गठजोड़ ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिलाया। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा जैसे नारों ने उस सामाजिक प्रयोग को राजनीतिक भाषा दी। लेकिन 2007 के बाद वह सामाजिक इंजीनियरिंग स्थायी राजनीतिक मॉडल नहीं बन सकी। दूसरी तरफ दलित समाज के भीतर नई पीढ़ी का नेतृत्व उभरा।

चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने आंदोलन की राजनीति के जरिए युवा दलितों के बीच जगह बनाई। बसपा के सामने अब चुनौती केवल भाजपा और सपा नहीं, बल्कि अपने ही पारंपरिक सामाजिक आधार के भीतर उभरती नई राजनीति भी है।

मायावती की राजनीति का एक समय सबसे बड़ा आकर्षण उनका आक्रामक आत्मविश्वास था। वह विरोधियों को सीधे चुनौती देती थीं। दलित सम्मान, सामाजिक हिस्सेदारी और सत्ता में प्रतिनिधित्व उनके भाषणों के केंद्रीय विषय रहे। उनकी राजनीति का मूल संदेश साफ था कि जिस समाज की संख्या अधिक है, उसे सत्ता में उसकी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। इसी सोच ने बाद में जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसे राजनीतिक संदेशों को ताकत दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मायावती की राजनीतिक भाषा बदलते समय के साथ बदल रही है?

2012 में सत्ता गंवाने के बाद बसपा की गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उसे बड़ा झटका लगा। 2019 में सपा के साथ गठबंधन ने बसपा को लोकसभा में 10 सीटें जरूर दिलाईं, लेकिन यह प्रयोग लंबे समय तक नहीं चला। 2022 के विधानसभा चुनाव तक तस्वीर और बदल चुकी थी। पार्टी का वोट आधार सिकुड़ता दिखाई दिया और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या बसपा का पुराना सामाजिक समीकरण टूट रहा है?

डोकलाम तक पहुँचेगी रेल, चीन के छूटे पसीने

नीरज कुमार दुबे

भारत ने चीन से सटी अपनी सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक पर सामरिक बढ़त हासिल करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने उत्तर बंगाल में खुनिया मोड़ (चालसा) से जलढाका तक 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी है, जिस पर करीब 272 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पहली नजर में यह परियोजना उत्तर बंगाल के डुआर्स क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय संपर्क बढ़ाने की पहल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे कहीं अधिक गहरे सामरिक और रणनीतिक निहितार्थ छिपे हैं। यह रेलवे लाइन भारत-चीन-भूटान त्रि-जंक्शन के करीब स्थित उस इलाके तक पहुंच मजबूत करेगी, जो डोकलाम विवाद के कारण वर्षों से राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र बना हुआ है।

रेल मंत्रालय से स्वीकृत इस परियोजना के तहत प्रस्तावित रेलवे लाइन चालसा के निकट खुनिया मोड़ से शुरू होकर जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग के वन क्षेत्रों से गुजरते हुए जलढाका तक पहुंचेगी। रेलवे और पश्चिम बंगाल वन विभाग मानसून के बाद इस परियोजना का संयुक्त सर्वेक्षण शुरू करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों तक बेहतर पहुंच, पर्यटन को बढ़ावा देना तथा सामरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

दरअसल, जलढाका नदी का महत्व केवल भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। यह नदी सिक्किम के कुपुप (बितांग) झील से निकलती है, जो जेलेप ला दर्रे के निकट और डोकलाम त्रि-जंक्शन के बेहद करीब स्थित है। यही कारण है कि नदी के समानांतर रेलवे लाइन विकसित करने की योजना को मात्र एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि सीमा क्षेत्रों में भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

इस परियोजना का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारतीय रेलवे पहले से ही चालसा

से सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर लगभग 200 किलोमीटर लंबी एक रणनीतिक रेलवे लाइन की संभावनाओं पर काम कर रहा है। नई 17 किलोमीटर की लाइन उसी व्यापक रणनीतिक दृष्टि का पहला महत्वपूर्ण चरण मानी जा रही है। यदि भविष्य में यह नेटवर्क आगे बढ़ता है तो भारत की सैन्य और नागरिक दोनों प्रकार की आवाजाही सीमा के बेहद करीब तक पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज, सुरक्षित और प्रभावी हो सकेगी।

देखा जाये तो डोकलाम का सामरिक महत्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वर्ष 2017 में यहीं 73 दिनों तक भारत और चीन की सेनाएं आमने-सामने खड़ी रहीं थीं। चीन भूटान के दावे वाले क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रहा था, जिसे रोकने के लिए भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया था। भारत और भूटान के बीच सुरक्षा सहयोग के तहत नई दिल्ली ने स्पष्ट किया था कि डोकलाम में यथास्थिति बदलने की किसी भी कोशिश का असर भारत की सुरक्षा, विशेषकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पड़ेगा। अंततः चीन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसके बाद से उपग्रह तस्वीरों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह सामने आता रहा है कि चीन ने डोकलाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में सड़कें, सैन्य ढांचे, गांव और अन्य आधारभूत संरचनाएं लगातार विकसित की हैं।

ऐसे समय में भारत द्वारा सीमा के समीप रेलवे अवसंरचना का विस्तार स्पष्ट संकेत देता है कि नई दिल्ली अब केवल सैन्य तैनाती के भरोसे नहीं, बल्कि मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क के जरिए भी सामरिक संतुलन स्थापित करना चाहती है। किसी भी संभावित संकट की स्थिति में सैनिकों, हथियारों, रसद और राहत सामग्री को तेजी से सीमा तक पहुंचाने में रेलवे की भूमिका सड़क मार्ग की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होती है। यही कारण है कि आधुनिक युद्ध और सीमा सुरक्षा में रेलवे को रणनीतिक शक्ति का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।

साथ ही इस परियोजना को सिक्किम में निर्माणाधीन शिवोक-रंगपो रेलवे लाइन के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना भविष्य में इस लाइन को नाथू ला दर्रे तक विस्तारित करने की है। यदि ऐसा होता है तो उत्तर-पूर्व और पूर्वी हिमालयी सीमाओं पर चीन के सामने भारत का यह दूसरा बड़ा रणनीतिक रेल कॉरिडोर होगा। इससे भारत की पूर्वी सीमा पर सैन्य तैयारियों और आपूर्ति श्रृंखला को नई मजबूती मिलेगी।

बहरहाल, यह स्पष्ट है कि जलढाका रेलवे परियोजना सिर्फ 17 किलोमीटर की रेल लाइन नहीं है। यह उत्तर बंगाल में विकास, पर्यटन और सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम तो बनेगी ही, साथ ही चीन की लगातार बढ़ती सीमा अवसंरचना के जवाब में भारत की बदलती रणनीतिक सोच का भी सशक्त प्रतीक साबित होगी। संदेश स्पष्ट है कि भारत अब सीमा पर केवल निगरानी नहीं, बल्कि मजबूत बुनियादी ढांचे के जरिए दीर्घकालिक सामरिक बढ़त सुनिश्चित करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है।

भाजपा को हाल की घटनाओं से सबक लेने का समय

विपिन पब्बी

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के लिए 'एक फूल से बहार नहीं आती' वाली कहावत बिल्कुल सही बैठती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इसे मामूली समझकर नजरअंदाज करना बड़ी गलती होगी। उपचुनाव के नतीजे, जिसमें पार्टी की अपनी सरकार वाले राज्य की दतिया सीट पर हार भी शामिल है, निश्चित रूप से उस पार्टी के लिए एक झटका है, जो हाल के दिनों में लगातार जीत हासिल कर रही थी। जरूरी नहीं कि विधानसभा उपचुनाव लोगों का आम मूड दिखाए लेकिन आम तौर पर रुझान सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में होता है, खासकर तब, जब केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार हो। जाहिर है, वोटर मानते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक को चुनने से उनके इलाके और सरकारी मदद चाहने वाले लोगों को फायदा होगा।

पटना के बीचों-बीच और उस राज्य में उपचुनाव का नतीजा, जहां भाजपा ने कुछ ही महीने पहले बड़ी जीत हासिल की थी, निश्चित रूप से भाजपा के लिए शर्मनाक होगा। सत्ताधारी पार्टी के लिए यह और भी शर्मनाक है क्योंकि यह उपचुनाव उसके नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की खाली की गई सीट पर हुआ था। पार्टी ने पिछले 3 दशकों से इस सीट पर कब्जा बनाए रखा था और नबीन ने लगातार 5 बार यहां जीत हासिल की थी। दूसरी ओर, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। उसने जिन 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन सभी पर उसे हार मिली और 236 सीटों पर तो उसकी जमानत तक जब्त हो गई। पार्टी को सिर्फ 3 फीसदी वोट मिले, जबकि प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव नहीं लड़ा था।

जंतर-मंतर पर छात्रों के ऐतिहासिक आंदोलन , जो पटना समेत दूसरे शहरों में भी फैल गया था, के कुछ ही दिनों बाद आए उपचुनाव के नतीजों पर निश्चित रूप से युवाओं के असंतोष का असर पड़ा। छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने से वे और भी नाराज हो गए थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफी देर से इस्तीफे और सरकार व छात्र प्रतिनिधियों के बीच बातचीत से आखिरकार आंदोलन पर रोक तो लगी लेकिन साफ है कि इस मामले में अभी आखिरी बात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

इन घटनाओं को लेकर गंभीर रूप से चिंतित थे और उन्होंने उन लोगों को माफ करके अच्छा किया, जिन्होंने उन्हें अपशब्द कहे थे। गाली-गलौच को सही नहीं ठहराया जा सकता लेकिन उन्हें सजा देना या परेशान करना भी सही रास्ता नहीं था। उनके स्वागत-योग्य दखल ने यह माना कि ऐसी हरकतों से मुकद्दमा चलाकर या जबरदस्ती से नहीं, बल्कि बातचीत और संबंधित लोगों तक पहुंचकर ही निपटा जा सकता है। हालांकि, उनका संदेश उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्त्ताओं और समर्थकों तक नहीं पहुंचा। उनमें से कुछ ने आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ जहरीला अभियान छेड़ दिया है। वे खास तौर पर महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। इनमें से कुछ छात्रों की संपर्क जानकारी जान-बूझकर लीक कर दी गई, जिससे उन पर शारीरिक हमले का खतरा बढ़ गया है। एक 15 साल की लड़की को कैमरे पर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया और लगातार मिल रही धमकियों के कारण उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। एक वायरल वीडियो में पार्टी का एक नेता आंदोलन में शामिल छात्रों को धमकी देता हुआ दिखाई दिया।

प्रधानमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इन गैर-जिम्मेदार ट्रोलर्स तक सही संदेश पहुंचाने के लिए आगे आना चाहिए। युवाओं की तरफ से किसी और विरोध-प्रदर्शन से बचने के लिए उन्हें रोकना जरूरी है। इसी तरह, कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भी आंदोलन में शामिल छात्रों की फाइलें या रिकॉर्ड बनाने से बचना चाहिए। पार्टी कई वजहों से मुश्किल में फंस गई है, जिनमें छात्रों का आंदोलन, उपचुनावों में हार, राम मंदिर और कुछ अन्य मंदिरों में 'चंदा चोरी' के सबूत और अंदरूनी कलह शामिल हैं। उसे फिर से सोचना होगा और बिना किसी पूर्वाग्रह के यह विश्लेषण करना होगा कि क्या गलत हो रहा है। इसके लिए उसे सबसे पहले अपना अहंकार छोड़ना होगा और लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के और रास्ते खोलने होंगे।

क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां क्यों थी।

संख्या पढकर चौंक गए परंतु यह सत्य है, शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी। वास्तव में उनकी 16,108 पत्नियां थी। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में बहुविवाह प्रथा बहुत लोकप्रिय थी, फिर भी 16,108 की संख्या बहुत अधिक लगती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में कई ऐसी कहानियाँ हैं जो काफी रोचक हैं। भगवान कृष्ण अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं जिनकी रोचक कहानियाँ हमारे मन में कुतूहल उत्पन्न करती है। राधा के साथ उनका आत्मिक प्रेम, आठ सुन्दर राजकुमारियों से विवाह तथा फिर भी 16,000 और अधिक पत्नियां निश्चित रूप से हमें आश्चर्यचकित कर यह जानने के लिए मजबूर कर देते हैं कि इन सब के पीछे क्या कारण होगा। यदि हम शास्त्रों में देखें तो हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण से राधा से कभी भी विवाह नहीं किया था।

क्यूं पड गया श्री कृष्ण के शरीर का रंग नीला परन्तु उन्होंने आठ महिलाओं से शादी की। उनकी आठ पत्नियों के नाम रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नाग्नाजिती, भद्रा और लक्ष्मणा थे। उनमें से सत्यभामा और रुक्मिणी प्रसिद्ध हैं। अब 16,000 पत्नियों की कहानी की ओर बढते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण एक चमत्कारी राजा थे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई न कोई कारण था। अत: यह कहना सही नहीं होगा कि 16,108 पत्नियां कृष्ण लीला का एक हिस्सा थी। अत: ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि भगवान कृष्ण को 16,000 महिलाओं से विवाह करना पडा आइए देखें।

महाभारत से जुडे कुछ रोचक रहस्य नरकासुर की कहानी नरकासुर प्रग्ज्योतिषा का राजा था। यह स्थान अब असम के नाम से जाना जाता है। वह विष्णु के सूअर अवतार वराह और पृथ्वी की देवी भूमि देवी का पुत्र था। भूमि का पुत्र होने के कारण उसे भौम या भौमासुर भी कहा जाता था। उसने स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों विश्व पर कब्जा कर लिया था। उसने पृथ्वी पर जिन 16,000 देशों पर विजय प्राप्त की थी उन देशों की राजकुमारियों को कैद कर लिया था।

स्वर्ग में उसने स्वर्ग और देवों के देव इंद्रदेव की मां अदिति के कान के बाले (इयररिंग) चुराए। पाताल में उसने पानी के देवता वरुण का शाही छाता चुरा लिया। उसने राजकुमारियों को एक पर्वत पर बंदी बना कर रखा। इसी दौरान इंद्र ने अदिति के कान के बाले वापस लाने तथा विश्व को इस राक्षस की क्रूरता से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान कृष्ण से नरकासुर के साथ युद्ध करने की याचना की। अत: भगवान कृष्ण ने राक्षस का वध कर दिया। लूट का माल नरकासुर की मृत्यु के पश्चात भूमि देवी ने सभी चुराई हुई चीजें कृष्ण को वापस कर दीं जिसमें 16,000 महिलायें भी शामिल थी। श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कर दिया परन्तु उन महिलाओं से इसका पालन नहीं किया।

सामाजिक कलंक प्राचीन काल में जब कोई राजा किसी अन्य राज्य की महिला का अपहरण कर लेता था तो राजा के परास्त होने के बाद भी उस महिला को राज्य में वापस नहीं लिया जाता था। उन्हें एक कलंकित और शर्मनाक जीवन व्यतीत करना पडता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उन्हें स्पर्श किया है। नरकासुर की कैद में रहने वाली 16,108 महिलाओं को भी यह सहन करना पडा। अत: उन सभी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। 16,108 पत्नियां अत: भगवान कृष्ण ने उन सभी से विवाह कर लिया। भागवत पुराण में विवाह के बाद कृष्ण की पत्नियों के जीवन के बारे में बताया गया है। प्रत्येक पत्नी को एक घर और सौ दासियाँ दी गयी थीं। कृष्ण ने स्वयं को कई रूपों में बाँट लेते थे तथा इस प्रकार रात में प्रत्येक पत्नी के साथ रहते थे। सुबह उनके सभी रूप मिलकर कृष्ण बन जाते और वे द्वारका के राजा रूप में आ जाते। कृष्ण की प्रत्येक पत्नी व्यक्तिगत तौर पर उन्हें नहला कर, सजा कर, पंखा झलकर, उन्हें उपहार और फूलों की माला देकर उनकी पूजा करती थी।

चमत्कारी राजा एक कथा के अनुसार एक बार उपद्रवी मुनि नारद ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपनी पत्नियों में से एक पत्नी उन्हें दे दें क्योंकि वे कुंवारें हैं। कृष्ण ने उनसे कहा कि आप किसी भी पत्नी को उस समय जीत कर दिखाएँ जब मैं (कृष्ण) उनके साथ न रहूँ। नारद कृष्ण की सभी 16,108 पत्नियों के घर गए परन्तु सभी घरों में कृष्ण उपस्थित थे। इस पारकर नारद कुवारें रह गए। इस घटना को देखकर नारद आश्वस्त हो गए कि भगवान कृष्ण के रूप में एक देवत्व था, एक पूर्ण और विविध आकार वाली अभिव्यक्ति जो एक ही समय में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ का आनंद उठा रही थी। यही कारण है कि भगवान कृष्ण को सर्वशक्तिमान माना जाता है जो किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के साथ रहते हैं जैसे वे अपनी 16,108 पत्नियों के साथ रहते थे।

कुंडली में मांगलिक दोष निवारण के उपाय

मांगलिक दोष क्या है।

जन्मपत्री की कुंडली में 12 स्थान होते हैं। इनमे से यदि पहले, दुसरे, चौथे, सातवे, आठवे और बारहवें स्थान में मंगल होता है तो मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष वाले व्यक्ति पर मंगल गृह की बुरी छायां होती है। यह प्रभाव शादी के समय बहुत मायने रखता है क्यों कि शादी के समय कुंडली मिलान का यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। शादी से पहले व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष को देखना और इसका निवारण करना जरूरी है।

मांगलिक दोष के लक्षण

1. स्त्री और पुरुष दोनों में मांगलिक दोष हो सकता है।

2. मंगल को उग्रता वाला गृह माना जाता है इसलिए मांगलिक दोष वाले लोगों का स्वाभाव गर्म माना जाता है।

3. मांगलिक लोगों में बहुत गर्म और उग्र ऊर्जा होता है जिसका यदि सही इस्तेमाल नहीं किया जाए तो यह कुछ ना कुछ गलत हो सकता है।

4. मांगलिक दोष के कारण शादी में देरी होती है।

5.मंगल दोष के कारण शादी में कलह और तनाव रहता है।

6. दो मांगलिक लोगों का आपस में विवाह करने से इसका बुरा प्रभाव दूर होता है।

7. ऐसा माना जाता है कि जिन्होंने पिछले जन्म में अपने पार्टनर के साथ बुरा किया उनमें यह दोष पाया जाता है।

मंगल कब समस्या पैदा करता है

1.यदि मंगल पहले स्थान में है तो शादी के बाद विवाद और हिंसा की सम्भावना रहती है।

2. जब मंगल दुसरे स्थान में रहता है तो व्यक्ति के परिवार के कारण उसका विवाह और नौकरी पेशा प्रभावित होता है।

3. जब मंगल चौथे स्थान में रहता है तो व्यक्ति व्यावसायिक तौर पर सफलता प्राप्त नहीं करता है और लगातार जॉब बदलता है।

4. यदि मंगल सातवे स्थान में होता है तो उसका स्वाभाव उग्र होता है, जिसके कारण वह अपने परिवार से भी मधुर सम्बन्ध नहीं रख पाता है।

5. यदि मंगल आठवे स्थान में होता है तो वह व्यक्ति परिवारजनों द्वारा अलग कर दिया जाता है और जायदाद से बेदखल हो जाता है।

6. जब मंगल दसवे स्थान में होता है तो व्यक्ति को दिमाग से सम्बंधित समस्याएं होती है साथ ही इससे दुश्मन पैदा होना या आर्थिक नुकसान जैसी चीजें भी हो सकती हैं।

मांगलिक दोष निवारण के उपाय

1. दो मांगलिक लोगों का विवाह करने से इसका प्रभाव खत्म हो जाता है।

2. कुम्भ विवाह भी इसका एक समाधान है। इस विवाह में व्यक्ति को शादी से पूर्व किसी पेड से या कलश से विवाह करना पडता है।

3. मंगलवार का व्रत करने से भी इसका बुरा प्रभाव कम होता है। इस व्रत में मांगलिक लोगों को तूर दाल ही खानी होती है।

4. मंगलवार को नवग्रह मन्त्र या हनुमान चालीसा का जाप करने से भी मांगलिक दोष का असर कम होता है।

5. मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करना भी मंगल दोष के निवारण का अच्छा उपाय है।

6. ज्योतिषियों के अनुसार मांगलिक दोष वाले लोगों को लाल मूंगा जडित सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करनी चाहिए।

7. मांगलिक लोगों को 28 साल की उम्र के बाद शादी करने की सलाह दी जाती है क्यों कि उम्र के अनुसार दोष का असर भी कम हो जाता है।

हिंदू धर्म में सिंदूर का महत्व

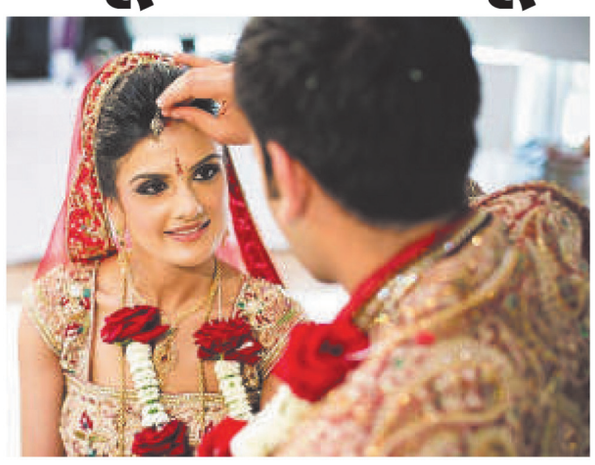

आमतौर पर सिंदूर को हिंदू महिलाओं द्वारा लगाया जाता है तथा इसका महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं में छुपा है। सिंदूर, एक स्त्री के विवाहित होने की निशानी है तथा इसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते लगाती हैं। इसे माथे पर बालों के बीच में लगाया जाता है।

हिंदू धर्म में, इसे लगाने का हक केवल विवाहित महिलाओं को दिया गया है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार, देवी पार्वती ने अपने पति के सम्मान के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी जिसके कारण सिंदूर को देवी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। अत:, माना जाता है कि जो महिला अपने माथे पर सिंदूर धारण करती है, देवी पार्वती का हाथ उसके सर पर सदैव बना रहता है तथा देवी पार्वती हर समय उसके पति की रक्षा करती है।

भारतीय महिलाएं क्यूं पहनती हैं नोज रिंग इसके अलावा सिंदूर धारण करने के कई ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद हैं। तो चलें, उन महत्वपूर्ण कारणों के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं।

1 ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, मेष राशि का स्थान माथे पर होता है। मंगल, मेष राशि का स्वामी ग्रह है और क्योंकि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, इसे शुभ माना जाता है। अत: इसे सौभाग्य का संकेत भी माना जाता है।

2 सिंदूर को नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह शक्ति एक पत्नी को किसी भी मुश्किल घडी में अपने पति की रक्षा करने में मदद करती है।

3 उत्तर भारत में नवरात्रि व संक्रांति के त्योहारों पर विवाहित स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाना अत्यंत अनिवार्य है। इससे पता चलता है कि सिंदूर धार्मिक कारणों की वजह से भी बहुत महत्व रखता है। हिंदू परंपराओं के पीछे छुपा हुआ है ये विज्ञान

4 सिंदूर लगाने का एक और दिलचस्प कारण भी है। सिंदूर को धातु पारे के साथ हल्दी व चूने के मिश्रण से तैयार किया जाता है। पारा रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है एवं महिलाओं की यौन इच्छा को सक्रिय करता है। जिसके कारण इसमें एक शारीरिक महत्व भी शामिल हो जाता है। इसलिए सिंदूर को हमारी भावनाओं के केन्द्र, पिट्यूटरी ग्रंथ पर लगाना चाहिए।

धन का संचय उतना ही करना चाहिए जितनी जरूरत हो

बात उस समय की है जब गुरु नानक देव लाहौर यात्रा पर थे। वह एक अजीब नियम था। वो यह कि जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक संपत्ति वह अपने घर के ऊपर उतने ही झंडे लगाता था लाहौर में दुनीचंद्र के पास 20 करोड रुपए की संपत्ति थी। इसलिए उसके घर की छत पर 20 झंडे फहरा रहे थे। दुनीचंद्र को पता चला कि गुरु नानक जी लाहौर आए हैं तो वो उनसे मिलने गया। दुनीचंद्र ने गुरुनानक जी से सेवा का अवसर मांगा। गुरु नानक जी ने उसे एक सुई देते हुए कहा, इसे ले जाइए और अगले जन्म में मुझे वापस कीजिएगा। दुनीचंद्र ने सुई ले ली। लेकिन उसने सोचा कि अगले जन्म में यह सुई मैं कैसे ले जा सकूंगा। वह वापस गुरु नानक जी के पास गया और उसने कहा, मरने के बाद में यह सुई कैसे ले जा सकता हूं। तब गुरु नानक जी ने कहा, जब तुम एक सुई अपने अगले जन्म में नहीं ले जा सकते तो इतनी सारी संपत्ति कैसे ले जा सकोगे। दुनीचंद्र ने जब यह बात सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं।

राहु दोष दूर करने के आध्यात्मिक उपाय

हिंदु धर्म में राहु और केतू दो ग्रह हैं जिन्हे दोष के रूप में जाना जाता है। राहु और केतू, एक ही असुर का नाम है जिसने अमृत मंथन के दौरान छल से अमृत पी लिया था और जब उसने आधा अमृत पी लिया तब पता चला कि वह असुर है तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। वह मरा नहीं, लेकिन सिर और धड दो हिस्सों में बंट गया, जिसे राहु-केतु के नाम से जाना गया। ये एक ग्रह बन गए जो लोगों की कुंडली में दोष माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इन्हे दूर करने के कई उपाय हैं, जिन्हे लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते है कि जीवन से राहु-केतु का दोष किस प्रकार दूर करना है। तो इन आध्यात्मिक उपायों को जानें।

राहु दोष दूर करने के आध्यात्मिक उपाय

प्रत्येक शनिवार शाकाहारी भोजन करें: राहु और केतू दोष ग्रह है। इसके लिए आपको शनिवार को पूजा क रनी चाहिए और इस दिन पूर्णत: शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए।

भगवान शिव की पूजा करें: अगर आपकी कुंडली में राहु-केतू का दोष है तो भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव, राहु-केतू और शनि के दोषों का निवारण करते है। आप प्रतिदिन 21 बार ओउम् नम: शिवाय का जाप करें। राहु शांति पूजा का प्रदर्शन करें: राहु और केतू के दोषों को शांत करने के लिए आप राहु शांति पूजा का प्रदर्शन करें। इस पूजा को आप घर पर आयोजित करवाएं, इससे आपके घर में सुख और शांति भी आएगी। श्रीकलाहस्ती मंदिर के दर्शन करें: श्रीकला हस्ती मंदिर आंध्रप्रदेश में स्थित है। जिन लोगों के जीवन में राहु-केतू दोष है वह इस मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य जाएं। साल में भारी संख्या में लोग यहां दर्शन करने आते है।

दान: राहु-केतू दोष होने पर आप शनिवार को सरसों का तेल दान करें, गेहूं, नारियल, केला आदि को दान करें। गरीबों को भोजन खिलाएं। इससे आपको जीवन में सुकून और खुशी मिलेगी और यह ग्रह दोष भी शांत हो जाएगा।

भोले के भैरव रूप के स्मरण से दूर होते हैं कष्ट

-**पहली** फरवरी को है कालाष्टमी

-रात्रि को जागरण कर शिव एवं माता पार्वती की कथा एवं भजन कीर्तन करें

-ब्रहमा के अपमानित करने पर शिव भगवान ने धारण किया था रौद्र रूप

कालाष्टमी का हिंदू धर्म में बडा महत्वपूर्ण स्थान है। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान शिव, भैरव रूप में प्रकट हुए थे। कालाष्टमी का व्रत इसी उपलक्ष्य में किया जाता है। कालाष्टमी को 'भैरवाष्टमी' के नाम से भी जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ के भैरव रूप के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। भैरव की पूजा व उपासना से मनोवांछित फल मिलता है। अत: भैरव जी की पूजा-अर्चना करने व कालाष्टमी के दिन व्रत एवं षोड्षोपचार पूजन करना अत्यंत शुभ एवं फलदायक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कालभैरव का दर्शन एवं पूजन मनवांछित फल प्रदान करता है।

व्रत की विधि भगवान शिव के भैरव रूप की उपासना करने वाले भक्तों को भैरवनाथ की षोड्षोपचार सहित पूजा करनी चाहिए और उन्हें अर्घ्य देनी चाहिए। रात्रि के समय जागरण कर शिव एवं पार्वती की कथा एवं भजन कीर्तन करना चाहिए। भैरव कथा का श्रवण और मनन करना चाहिए। मध्य रात्रि होने पर शंख, नगाडा, घंटा आदि बजाकर भैरव जी की आरती करनी चाहिए। भगवान भैरवनाथ का वाहन 'श्वान' (कुत्ता) है। अत: इस दिन प्रभु की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन प्रात:काल पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर पितरों का श्राद्ध व तर्पण कर भैरव जी की पूजा व व्रत करने से समस्त विघ्न समाप्त हो जाते हैं। भैरव जी की पूजा व भक्ति से भूत, पिशाच एवं काल भी दूर रहते हैं। शुद्ध मन एवं आचरण से जो भी कार्य करते हैं, उनमें इन्हें सफलता मिलती है।

माहात्म्य कालाष्टमी के दिन काल भैरव के साथ इस दिन देवी कालिका की पूजा-अर्चना एवं व्रत का भी विधान है। काली देवी की उपासना करने वालों को अर्धरात्रि के बाद मां की उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए, जिस प्रकार दुर्गापूजा में सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। भैरव की पूजा-अर्चना करने से परिवार में सुख-शांति, समृद्धि के साथ स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है। भैरव तंत्रोक्त, बटुक भैरव कवच, काल भैरव स्तोत्र, बटुक भैरव ब्रहम कवच आदि का नियमित पाठ करने से अनेक समस्याओं का निदान होता है।

कथा भैरवाष्टमी या कालाष्टमी की कथा के अनुसार एक समय श्रीहरि विष्णु और ब्रहमा के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इस हद तक बढ गया कि समाधान के लिए भगवान शिव एक सभा का आयोजन करते हैं। इसमें ज्ञानी, ऋषि-मुनि, सिद्ध संत आदि उपस्थित थे। सभा में लिए गए एक निर्णय को भगवान विष्णु तो स्वीकार कर लेते हैं, किंतु ब्रहमा जी संतुष्ट नहीं होते। वे महादेव का अपमान करने लगते हैं। शांतचित शिव यह अपमान सहन न कर सके और ब्रहमा द्वारा अपमानित किए जाने पर उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर प्रलय के रूप में नजर आने लगे और उनका रौद्र रूप देखकर तीनों लोक भयभीत हो गए। भगवान शिव के इसी रूद्र रूप से भगवान भैरव प्रकट हुए। वह श्वान पर सवार थे, उनके हाथ में दंड था। हाथ में दंड होने के कारण वे 'दंडाधिपति' कहे गए। भैरव जी का रूप अत्यंत भयंकर था। उनके रूप को देखकर ब्रहमा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान भोलेनाथ एवं भैरव की वंदना करने लगे। ब्रहमा, देवताओं और साधुओं द्वारा वंदना करने पर भैरव जी शांत हो जाते हैं।

क्यूं की जाती है गणेश-लक्ष्मी की पूजा एक साथ

दीपावली के दिन हम धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी और बुद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। यह हम सब भली भांती जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य गणेश पूजन के बगैर कभी पूरा नहीं होता।

गणेश जी बुद्धि प्रदान करते हैं। वे विघ्न विनाशक और विघ्नेश्वर हैं। यदि व्यक्ति के पास खूब धन-सम्पदा है और बुद्धि का अभाव है तो वह उसका सदुपयोग नहीं कर पायेगा। इसलिए व्यक्ति का बुद्धिमान और विवेकी होना भी आवश्यक है। तभी धन के महत्व को समझा जा सकता है। गणेश लक्ष्मी की एक साथ पूजा के महत्त्व को कई कहानियों के माध्यम से बताया गया है। आइये जाने ऐसी ही कहानी।

शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी को धन और संब्रद्धि का प्रतीक माना गया है। जिसकी वजह से लक्ष्मी जी को इसका अभिमान हो जाता है। विष्णु जी इस अभिमान को खत्म करना चाहते थे इसलिए उन्हों ने लक्ष्मी जी से कहा कि स्त्री तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक वह माँ ना बन जाये। लक्ष्मी जी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए यह सुन के वे बहुत निराश हो गयी। तब वे देवी पार्वती के पास गयी मदद मांगने के लिए।

जानिए दीवाली पर क्यों किया जाता है लक्ष्मी पूजन

पार्वती जी को दो पुत्र थे इसलिए लक्ष्मी जी ने उनसे एक पुत्र को गोद लेने को कहा। पार्वती जी जानती थी कि लक्ष्मी जी एक स्थान पर लंबे समय नहीं रहती हैं। इसलिए वे बच्चे की देख भाल नहीं कर पाएंगी। लेकिन उनके दर्द को समझते हुए उन्होंने अपने पुत्र गणेश को उन्हें सौप दिया।

इससे लक्ष्मी जो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि वे गणेश का बहुत ध्यान रखेंगी। और जो सुख और संब्रद्धि के लिए लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं उन्हें उनसे पहले गणेश जी की पूजा करनी पडेगी, तभी मेरी पूजा संपन्न होगी। तब से आज तक दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना

नईदिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में अपने देश लौटने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वह उचित समय पर अपनी वापसी की तारीख की घोषणा करेंगी. हसीना ने कहा कि उनका लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में पूरा विश्वास है. वापसी को लेकर उठ रही आशंकाओं पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सरकार जो चाहे करे, लेकिन उन्होंने दिसंबर में देश लौटने का फैसला कर लिया है.बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने के ठीक दो साल बाद, 5 अगस्त 2026 को शेख हसीना ने दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में पत्रकारों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया. इस दौरान उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था. उन्होंने केवल ऑडियो संदेश के जरिए अपनी प्रस्तावित वापसी की जानकारी साझा करते हुए कहा कि वह जल्द ही अपने अगले कदम की औपचारिक घोषणा करेंगी.पूर्व पीएम से जब पूछा गया कि अगर बांग्लादेश लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

परिसीमन के लिए विशेष सत्र बुला सकती है सरकार

नईदिल्ली। केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है. मौजूदा मॉनसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होना है, लेकिन इसके बाद सत्रावसान (प्रोरोगेशन) नहीं किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सके.बताया जा रहा है कि सरकार संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है. जैसे ही पर्याप्त समर्थन का भरोसा मिलेगा, 16 अगस्त से तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है. हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.सरकार की तरफ से कांग्रेस समेत विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव दिया गया है. सरकार ने कांग्रेस को कहा है कि सरकार 16,17,18 से संसद का विशेष सत्र परिसीमन बिल पर बुलाना चाहती है. सरकार के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों से चर्चा करके बताएंगे।

टारगेट किलिंग में लश्कर आतंकी लतीफ की तलाश

नईदिल्ली। कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के वांछित आतंकी मोहम्मद लतीफ भट की तलाश तेज हो गई है. श्रीनगर में उसके वांटेड पोस्टर लगाए गए हैं और गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले के लिए 15 लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया गया है.कश्मीर में हाल के दिनों में हुई टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है. इसी कड़ी में लश्कर-ए-तैयबा के वांछित आतंकी मोहम्मद लतीफ भट की तलाश तेज कर दी गई है. सुरक्षा बलों ने उसके खिलाफ आम लोगों से मदद लेने के लिए बड़ा कदम उठाया है. श्रीनगर के कई प्रमुख इलाकों में उसके वांटेड पोस्टर लगाए गए हैं, ताकि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाई जा सके और उसकी गिरफ्तारी में मदद मिल सके.श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव समेत शहर के कई व्यस्त इलाकों में सुरक्षा बलों ने मोहम्मद लतीफ भट के पोस्टर चिपकाए हैं।

19 राज्यों में कट सकते हैं एक करोड़ वोटर्स के नाम

नईदिल्ली। देश में वोटर लिस्ट को सही और साफ-सुथरा बनाने का काम तेजी से चल रहा है. निर्वाचन आयोग श्वष्ट ने देश के 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण स्ड्रक शुरू किया है. इस अभियान के दौरान वोटर लिस्ट से एक करोड़ बारह लाख से ज्यादा नाम कटने के आसार हैं. आयोग का मकसद फर्जी और गलत नामों को हटाकर लिस्ट को पूरी तरह सही करना है.दरअसल, चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट रोल और एसडीडीओपी सूची जारी की है. इसमें उन लोगों के नाम हैं जो अनुपस्थित हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, डुप्लीकेट हैं, जिनकी मौत हो चुकी है या फिर जो विदेशी हैं. ये वे लोग हैं जो अब देश के वैध वोटर नहीं रहे हैं. कई लोगों के नाम एक से ज्यादा जगहों की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं. ऐसे सभी नामों को लिस्ट से बाहर किया जा रहा है. देशभर में चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान अलग-अलग राज्यों में स्थिति काफी अलग देखने को मिल रही है।

मंत्री दीपक प्रकाश अब बने एमएलसी

नईदिल्ली। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत कर दिया गया है. राज्यपाल ने सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उनके मनोनयन पर मुहर लगा दी. इसके साथ ही अब वह विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे.दीपक प्रकाश को उस सीट पर मनोनीत किया गया है, जो बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. सरकार ने इस रिक्त सीट के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया था, जिस पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद मनोनयन की प्रक्रिया पूरी हुई.दीपक प्रकाश फिलहाल बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं. वह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं. लंबे समय से उनके किसी सदन का सदस्य न होने को लेकर राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर चर्चा होती रही थी. दीपक प्रकाश नवंबर 2025 में पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने थे. इसके बाद 8 महीने से ज्यादा समय तक वह विधानसभा और विधान परिषद, दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे।

कांग्रेस नेता के आरोपों पर पीयूष गोयल का पलटवार

राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जो उन्होंने जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए थे। 6 अगस्त को जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए गोयल ने कहा कि स्थिति को सही ढंग से संभाला गया था और ज़ोर देकर कहा कि कोई गलत काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। पूरी स्थिति को सही तरीके से संभाला गया। कोई गलत काम नहीं हुआ।

गोयल का यह बयान राहुल गांधी के उस आरोप के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात के बाद लोकतांत्रिक असहमति को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। प्रदर्शनकारियों से बातचीत के दौरान गांधी ने कहा कि उन्हें पुलिस की बर्बरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। उन्होंने उन रिपोर्टों का ज़िक्र किया जिनमें एक नाबालिग लड़की पर माफ़ी मांगने के लिए दबाव डाला गया था।

उन्होंने कहा कि पहले उन पर दबाव डालना, उनके घर गुंडे भेजना, ज़बरदस्ती 15 साल की लड़की से माफ़ी मंगवाना और फिर उस माफ़ी को स्वीकार करना - यह सब पूरी तरह बकवास है। हम इसे स्वीकार नहीं करते। हम एक ऐसा शिक्षा तंत्र चाहते हैं जो ठीक से काम करे, हम चाहते हैं कि परीक्षा के पेपर लीक होना बंद हों और हम चाहते हैं कि इस देश के भविष्य का सम्मान और सुरक्षा हो। गांधी ने विरोध-प्रदर्शन को संभालने के सरकार के तरीके की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई।

उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था - जो कि एक खराब, ढहती हुई और बेकार व्यवस्था है - के बारे में शिकायत करना कोई अपराध नहीं है। असल में, इस व्यवस्था को बदलने और ठीक करने की ज़रूरत है। वे बस यही मांग कर रहे थे। वे न तो हिंसा कर रहे थे, न ही आक्रामक या बदतमीज़ी से पेश आ रहे थे। फिर भी उन्हें पीटा गया, उन पर हमला किया गया और उन्हें धमकाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए गांधी ने पुलिस की कार्रवाई के लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया।

केजरीवाल के एथनॉल पर आरोपों को भाजपा ने बताया फर्जी खबर, किया पलटवार

नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के प्रमुख अमित मालवीय के बीच बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर उस समय तीखी नोकझोंक हुई, जब केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार डीजल और विमान टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) में भी एथनॉल मिलाने की योजना बना रही है। मालवीय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि ''फर्जी खबर'' फैलाना और बेवजह ''दहशत'' पैदा करना केजरीवाल की ''पुरानी आदत'' है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि ई20 से अधिक एथनॉल मिलाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है।

ई20 ऐसा ईंधन है, जिसमें 80 प्रतिशत पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथनॉल मिला होता है। ई20 देश के खुदरा ईंधन बाजार में बदलाव ला रहा है। केजरीवाल ने दावा किया कि सरकार जल्द ही डीजल में भी एथनॉल मिलाएगी।

उन्होंने लोगों से नये पेट्रोल और डीजल वाहन फिलहाल नहीं खरीदने की अपील की। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया कि मोदी सरकार विमान टर्बाइन ईंधन में भी एथनॉल मिलाने की योजना बना रही है। केजरीवाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि ई20 ईंधन व्यवस्था लागू करने के बाद सरकार पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा बढ़ाकर 50 प्रतिशत से अधिक करने की योजना बना रही है।

उन्होंने कहा, ''ऐसा पता चल रहा है कि वे पेट्रोल में 50 प्रतिशत से अधिक एथनॉल मिलाने वाले हैं। वे बस माहौल शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पहले आपकी ई0 और ई10 गाड़ियों में जबरन ई20 पेट्रोल डालकर उनका कबाड़ा कर दिया।

आज अगर आप नया ई20 वाहन खरीदते हैं तो सरकार कुछ समय बाद उसमें जबरदस्ती ई50 पेट्रोल डालकर उसका भी कबाड़ा कर देगी।'' पूर्व मुख्यमंत्री ने मालवीय को जवाब देते हुए आरोप लगाया कि सरकार ईंधन में और अधिक एथनॉल मिलाने से पहले स्थिति शांत होने का इंतजार कर रही है। केजरीवाल ने कहा, ''जिस तरह आपने किसी वैज्ञानिक अध्ययन के बिना, किसी की बात सुने बिना और धमकाकर सबको चुप कराते हुए ई20 लागू किया, उसी तरह आप ई50 भी लागू करेंगे।'' उन्होंने आरोप लगाया कि विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी पर गौर किए बिना काम करना सरकार की ''कार्यशैली'' है। केजरीवाल ने मालवीय को चुनौती दी कि ई20 पेट्रोल व्यवस्था लागू करने से पहले कराया गया कोई भी अध्ययन सार्वजनिक किया जाए।

मालवीय ने 'एक्स' पर एक अन्य पोस्ट में पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल का पूरा तर्क तथ्यों पर नहीं, बल्कि ''भय'' पर आधारित है। उन्होंने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा, ''पहली बात, सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि ई20 से अधिक एथनॉल मिश्रण बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया गया है। काल्पनिक ई50 पर बहस छेड़ना भय फैलाने की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है।'' मालवीय ने 'आप' नेता के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है कि ई20 को ''बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन'' के लागू किया गया।

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में दावा किया कि ई20 जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है और देश में एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम दो दशक से अधिक समय से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। मालवीय ने कहा कि ई20 लागू करने से पहले व्यापक परीक्षण किए गए और सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया गया। 'आप' ने ई20 पेट्रोल व्यवस्था को बढ़ावा देने की सरकार की नीति की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि एथनॉल मिश्रित ईंधन से वाहन मालिकों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष का अमित शाह से सीधा सवाल

पुलिस कार्रवाई पर राज्यसभा में आकर दें बयान: खड़गे

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह से 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बारे में सदन में बयान देने को कहा है। खड़गे ने सरकार पर 6 अगस्त की कार्यवाही के दौरान इस मामले पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। राज्यसभा में बोलते हुए, खड़गे ने सभापति से आग्रह किया कि वे गृह मंत्री को सदन को संबोधित करने का निर्देश दें।

उन्होंने कहा 15 दिन से सदन चल रहा है और गृह मंत्री गायब हैं, प्रधानमंत्री आ नहीं रहे हैं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक या तो वे संसद को नजरअंदाज कर रहे हैं ये समझ रहे हैं कि संसद है ही नहीं। या तो वो डर के सदन में आकर उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं।

खड़गे ने कहा कि हम देश और उसके 140 करोड़ लोगों से जुड़े वाजिब सवाल ही उठाते हैं। हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सदन में आने के लिए कह रहे हैं। हम सभापति से अनुरोध करते हैं कि वे गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देने का निर्देश दें। हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसी सदन में अरुण जेटली जी ने खुद कहा था कि कामकाज में रुकावट संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा है। आप कार्यवाही से जुड़े कोई भी सवाल उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ, जब हम वाजिब सवाल पूछ रहे हैं, तो वे बचकर निकल रहे हैं।

खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की पिछली टिप्पणियों की आलोचना की और संसद में कामकाज में बाधा डालने के मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की बातों का ज़िक्र किया। इसके जवाब में रिजिजू ने कहा कि खड़गे ने अपनी मांग के समर्थन में किसी नियम का हवाला नहीं दिया और ज़ोर देकर कहा कि विपक्ष कार्यवाही को तय नहीं कर सकता या यह तय नहीं कर सकता कि सरकार की ओर से कौन सा मंत्री जवाब देगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने किसी नियम का हवाला नहीं दिया। वे पीठासीन अधिकारी को निर्देश नहीं दे सकते। यह सरकार की सामूहिक ज़िम्मेदारी है। कांग्रेस को नए सदस्यों को भी मौका देना चाहिए।

राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने रिजिजू को निर्देश दिया कि वे विपक्ष की बात गृह मंत्री तक पहुंचाएं। सीपीआई सांसद पी. संतोष कुमार ने चेयरमैन के इस निर्देश को विपक्ष की जीत बताया और कहा कि यह पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत है। हम लगातार मांग कर रहे थे कि अमित शाह आएं और 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज पर बयान दें। अब आखिरकार, चेयरमैन ने रिजिजू को निर्देश दिया है कि वे विपक्ष की बात गृह मंत्री तक पहुंचाएं। हम उस जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत पाएगी टीम इंडिया?

नईदिल्ली। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में हर चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहने की सलाह दी है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होना है। इससे पहले, भारतीय टीम श्रीलंका इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच में हिस्सा लेगी, जिसकी शुरुआत सात अगस्त से होनी है। पहले टेस्ट की मेजबानी गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम करेगा, जबकि दूसरा टेस्ट मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो का सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान करेगा।

गंभीर ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में कहा, दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे सामने क्या है। हम जानते हैं कि हम किसके लिए खेल रहे हैं। हम जोर लगा सकते हैं, हम अपनी सीमा को पार कर सकते हैं, हम सभी चीजों को पूरा कर सकते हैं। 15 तारीख की सुबह, चाहे हम पहले बैटिंग कर रहे हों, या पहले गेंदबाजी कर रहे हों, हमें हर सवाल और हर जवाब के लिए पूरी तरह तैयार रहना है। इसलिए पक्का करें कि हम अभी से सभी चीजों को पूरा करें।

गंभीर ने नए खिलाड़ियों, ऑफ-स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर सारांश जैन और तेज गेंदबाज आकिब नबी का टेस्ट सेटअप में आधिकारिक तौर पर स्वागत किया। इसके साथ ही हेड कोच ने नए नियुक्त फील्डिंग कोच, सुभादीप घोष का भी स्वागत किया। गंभीर वीडियो में कहते हैं, दोस्तों, सभी का स्वागत है। हमारे साथ कुछ नए लोग आए हैं। सबसे पहले, सारांश, बधाई हो, आपने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। जब भी आपको मौका मिले, अपने परिवार और देश को गर्व महसूस कराना सुनिश्चित करें।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 374 अंक उछला निफ्टी 24,636 पर बंद

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, आरबीआई के स्थिर नीतिगत रुख और अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेतों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। इसके चलते बैंकिंग, ऊर्जा और चुनिंदा दिग्गज शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 374 अंक यानी 0.48% की तेजी के साथ 78,954.76 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी50 11.35 अंक यानी 0.05% बढ़कर 24,636.00 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी50 में रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वाले शेयर रहे। व्यापक बाजार की बात करें तो निफ्टी मिडकैप 0.44% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 0.48% की बढ़त दर्ज करने में सफल रहा। इससे साफ है कि चुनिंदा स्मॉलकैप शेयरों में निवेशकों की खरीदारी बनी रही।

मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स का आईपीओ 11 को खुलेगा

नई दिल्ली। डेयरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स लिमिटेड ने अपने 1,553 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए बृहस्पतिवार को 133-140 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया। यह निर्गम 11 अगस्त को खुलेगा। कंपनी ने सार्वजनिक सूचना में कहा कि आईपीओ 13 अगस्त को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया 10 अगस्त को एक दिन के लिए खुलेगी। प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम किसी भारतीय डेयरी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। आईपीओ में 1,428 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, 125 करोड़ रुपए तक के शेयर बिक्री पेशकश (ओएफएस) के तहत बेचे जाएंगे। इस प्रकार निर्गम का कुल आकार 1,553 करोड़ रुपए होगा।

एलआईसी में 6.5% हिस्सेदारी बेच सरकार ने जुटाए 31,522 करोड़

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में 6.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 31,522 करोड़ रुपए जुटाए। यह देश के पूंजी बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) रहा। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखते हुए अंजाम दिया, जिससे बाजार को अंतिम समय तक इसकी भनक नहीं लगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने ओएफएस की लॉन्च डेट को अंतिम समय तक गुप्त रखा ताकि ट्रेडर पहले से पोजीशन न बना सकें और शेयर की कीमत पर दबाव न पड़े। यही वजह रही कि सरकार शुरुआती योजना से कहीं अधिक हिस्सेदारी बेचने में सफल रही। सूत्रों के अनुसार, डील से जुड़े निवेश बैंकों को भी अलग-अलग समय पर जानकारी दी गई। एक बैंक को तो स्टॉक एक्सचेंज में सूचना जारी होने से कुछ समय पहले ही ओएफएस की जानकारी मिली।

एलन मस्क की नेटवर्थ में बड़ी गिरावट

वाशिंगटन। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की नेटवर्थ में बुधवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। स्पेसएक्स के शेयरों में 13.61% गिरावट आई जबकि टेस्ला का शेयर भी 1.77% लुढ़क गया। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक इससे मस्क की संपत्ति में 89.6 अरब डॉलर की गिरावट आई। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 85.7 अरब डॉलर से ज्यादा है। हालांकि, साल 2026 की शुरुआत से अब तक मस्क की संपत्ति में कुल 68.1 अरब डॉलर की बढ़ोतरी बनी हुई है। दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में से 8 की नेटवर्थ में गिरावट आई। मस्क के बाद सबसे ज्यादा नुकसान लैरी पेज को हुआ। गूगल के कोफाउंडर की नेटवर्थ 11.5 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 309 अरब डॉलर रह गई।

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता : निवेश सुरक्षा के बिना अधूरा रहेगा एफटीए

राजेश्वरी सेन गुप्ता

इस समय भारत के समक्ष सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती रोजगार के अच्छे अवसर तैयार करना है। हर वर्ष 1.0 से 1.2 करोड़ युवा श्रम बल में शामिल होते हैं। विनिर्माण क्षेत्र को रोजगार उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए थी लेकिन इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान पिछले दो दशकों से 15-17 फीसदी पर ही अटका हुआ है।

विनिर्माण बढ़ाने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होगी और इसके लिए केवल घरेलू बचत से काम नहीं चलने वाला है। भारत को पूंजी, तकनीक और रोजगार सृजित करने के लिए अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की दरकार है। हाल में हुआ भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) ऐसा करने का एक मौका देता है। मगर प्रश्न यह है कि क्या भारत इसका लाभ उठा पाएगा।

एफडीआई के आंकड़े चिंताजनक हैं। मीडिया में ज्यादातर चर्चा कुल आंकड़ों पर होती है मगर जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर भारत में आने वाला एफडीआई 1 फीसदी से भी कम हो गया है। यह वियतनाम और मलेशिया जैसी आसियान अर्थव्यवस्थाओं के 5.7 फीसदी के औसत से बहुत कम है। ये देश 'चीन+1' बदलाव से सबसे अधिक फायदा उठाने वाले देश रहे हैं जबकि बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत काफी पीछे छूट गया है। इसके अलावा, भारत में आने वाला अधिकतर एफडीआई विनिर्माण के बजाय सेवा क्षेत्र में जाता है जिससे रोजगार तैयार करने के लिहाज से इसका असर सीमित हो जाता है।

विनिर्माण में बड़े पैमाने पर वृहद स्तर पर एफडीआई आकर्षित करने के लिए नीति-निर्माताओं को अब वैश्विक कंपनियों को

अपने विस्तार के अगले चरण के लिए भारत को तरजीह देने के लिए मनाना होगा। मगर ऐसा करना आसान भी नहीं होगा। इसके लिए उन कारणों को दूर करना होगा जिनकी वजह से पिछले दशक में भारत निवेश के लिहाज से कम आकर्षक बन गया है।

एक अहम वजह निवेश सुरक्षा को लेकर बढ़ती अनिश्चितता रही है। वर्ष 2016 और वर्ष 2024 के बीच भारत ने 77 देशों (जिनमें 22 ईयू सदस्य देश शामिल हैं) के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते (बीआईटी) खत्म कर दिए और उनकी जगह अधिक सीमित 2015 मॉडल बीआईटी लागू किया। इन देशों से आने वाले नए निवेश के लिए अब वे सुरक्षा उपाय नहीं हैं जो बीआईटी में आम तौर पर मनमाने सरकारी कदम, भेदभावपूर्ण व्यवहार, बिना मुआवजे के जब्ती और अनिश्चित विवाद समाधान के खिलाफ होते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि विदेशी निवेशक आज भारत में निवेश करने को लेकर अधिक आश्वस्त नहीं लग रहे हैं।

इसके अलावा, भारत अब भी लगभग 16 फीसदी का औसत आयात शुल्क लगाता है जो आसियान देशों की तुलना में काफी अधिक है। हाल के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) कुछ चुनिंदा साझेदारों के लिए शुल्क कम करते हैं मगर ये उस व्यापक उदारीकरण का दूसरे सबसे अच्छे विकल्प हैं जिसकी वैश्विक स्तर पर जुड़े विनिर्माताओं को जरूरत है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के बढ़ते इस्तेमाल ने आयातित कच्चे माल तक पहुंच सीमित कर लागत और बढ़ा दी है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विकास के लिए निवेश सुविधा समझौता (आईएफडीए) से बाहर रहने का भारत का निर्णय यह धारणा और मजबूत करता है और ऐसे समय में सतर्कता का संकेत देता है जब वैश्विक निवेशक खुलेपन की तलाश में हैं। जब कंपनियां यह तय करती हैं कि अगला संयंत्र कहां लगाया जाए, तो ये रुकावटें मायने रखती हैं। निवेश सुरक्षा पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। उदाहरण के लिए व्यावसायिक विवाद अनुबंध से जुड़े मामले होते हैं। अगर कोई विदेशी निवेशक और उसका भारतीय साझेदार सिंगापुर या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मंच पर मध्यस्थता के जरिये उन्हें सुलझाने पर सहमत होते हैं तो सरकार को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकना चाहिए।

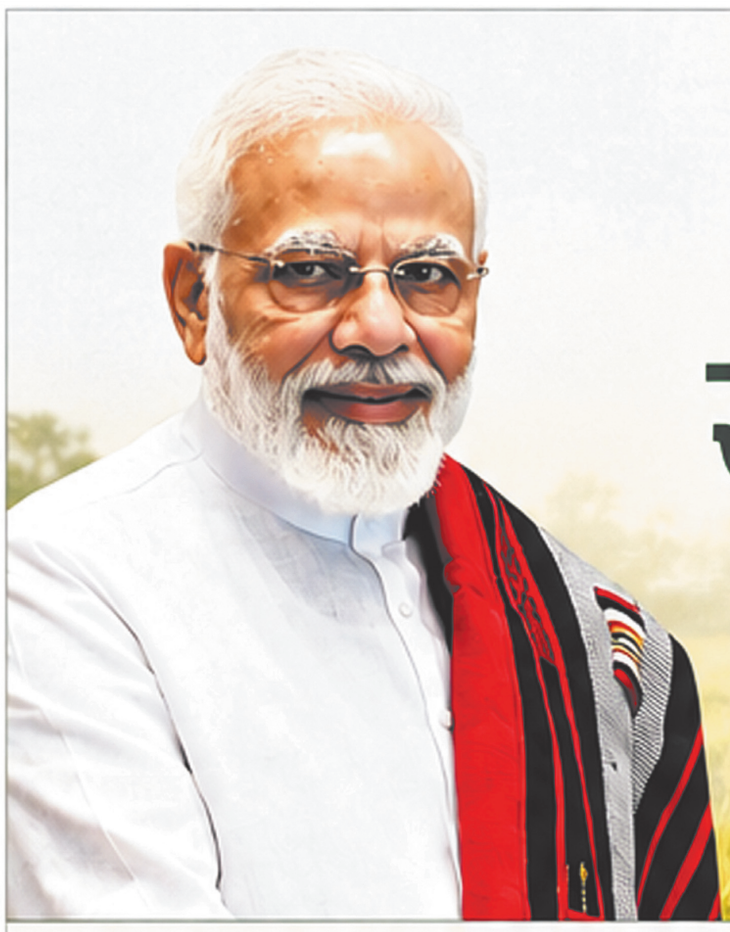

किसान नीतियों से खेतों में लौटी समृद्धि

किसानों की खुशहाली से मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था

छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी को नई दिशा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। गांव, गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता के केंद्र में हैं। कृषि जहां देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव मानी जाती है, वहीं छत्तीसगढ़ की पहचान भी खेती और किसानों से जुड़ी हुई है। धान का कटोरा कहलाने वाला यह राज्य आज फिर से कृषि समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते वर्षों में किसान हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर खेती-किसानी को नया संबल दिया है। सरकार की नीतियों का सबसे बड़ा असर प्रदेश के गांवों और खेतों में दिखाई दे रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, किसानों को आर्थिक सहायता, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देकर सरकार ने लाखों किसानों के जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया है। किसानों का विश्वास बढ़ा है और खेती फिर से लाभ का सौदा बनती दिखाई दे रही है।

खेती-किसानी बनी विकास की सबसे बड़ी ताकत

प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है। किसानों के खातों में हजारों करोड़ रुपए की सहायता राशि अंतरित की गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। खेती का रकबा बढ़ा है, उत्पादन में वृद्धि हुई है और बड़ी संख्या में किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और सरकार का स्पष्ट मानना है कि किसानों की खुशहाली से ही प्रदेश के विकास का रास्ता निकलेगा। यही कारण है कि खेती-किसानी को मजबूत करने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू की जा रही हैं।

प्रदेश में खेती-किसानी को मिला नया संबल

प्रधानमंत्री की गारंटी और किसान कल्याण का संकल्प

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की खुशहाली के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। खेती-किसानी को लाभकारी व्यवसाय बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं से किसानों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ सिंचाई, बिजली, बीज और तकनीकी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और गांवों को समृद्ध बनाने के लिए अनेक योजनाएं तेजी से लागू की जा रही हैं।

गांवों तक पहुंच रही योजनाओं की ताकत

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से किसानों का बढ़ा आत्मविश्वास

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को और अधिक मजबूत बनाया है। सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ निर्धारित सीमा तक धान खरीदी कर उन्हें बेहतर मूल्य उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है और ग्रामीण बाजारों में भी आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। सरकार ने धान खरीदी के साथ-साथ किसानों के पुराने लंबित बोनस का भुगतान कर लाखों परिवारों को बड़ी राहत दी है। किसानों का कहना है कि सरकार के फैसलों से खेती में फिर से भरोसा लौटा है और गांवों में आर्थिक खुशहाली का वातावरण बना है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला नया विस्तार

राज्य सरकार ने कृषि बजट में लगातार बढ़ोतरी करते हुए खेती, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस किया है। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ने से किसानों को आधुनिक संसाधनों का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में धान उत्पादन के साथ-साथ दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल धान खरीदी तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। यही वजह है कि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और कृषि आधारित छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

किसानों के लिए योजनाओं का बड़ा विस्तार

राज्य सरकार ने कृषि समृद्धि के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का विस्तार किया है। किसानों को कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास किया जा रहा है। फसल बीमा योजना, दलहन-तिलहन प्रोत्साहन, बीज उत्पादन एवं वितरण और कृषि विकास योजनाओं के माध्यम से किसानों को नई ताकत मिल रही है। सरकार की इन योजनाओं से खेती अब पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और लाभकारी बन रही है।

धान खरीदी में लगातार बन रहे नए कीर्तिमान

प्रदेश सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड स्तर पर धान खरीदी कर नया इतिहास बनाया है। लाखों किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिला है और खरीदी प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया गया है। धान खरीदी के एवज में किसानों को तेजी से भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। किसानों के खातों में सीधे राशि अंतरित होने से व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ी है।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से बढ़ा भरोसा

गांव-गांव तक पहुंच रही सिंचाई और तकनीक

प्रदेश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जहां बिजली सुविधा नहीं पहुंची है, वहां सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इससे दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के किसानों को भी खेती में बड़ी राहत मिली है। सरकार कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों को समन्वित रूप से आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। इससे किसानों और भूमिहीन मजदूरों दोनों की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है।

किसान सम्मान निधि से मिल रहा बड़ा सहारा

प्रदेश के लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। किसानों को प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे खेती की लागत में मदद मिल रही है। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल से किसानों को उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

खेती से ही मजबूत होगी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था

प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि का रास्ता खेती-किसानी से होकर गुजरता है। किसानों की आर्थिक मजबूती से व्यापार, उद्योग और ग्रामीण बाजारों में भी नई गति आती है। राज्य सरकार किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध करा रही है, जिससे खेती के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना आसान हुआ है। लाखों किसानों को सहकारी और ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसानों को साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा और खेती में निवेश बढ़ रहा है।

किसानों के हित में सरकार के बड़े फैसले

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठकों में किसानों के हित में लगातार महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। धान खरीदी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाया गया है।

- ऑनलाइन टोकन व्यवस्था, ई-केवाईसी, डिजिटल फसल सर्वे और बायोमैट्रिक सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं से वास्तविक किसानों को लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।
- खरीदी केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है।
- सरकार ने धान के अवैध परिवहन और गड़बड़ियों को रोकने के लिए भी मजबूत व्यवस्था लागू की है।
- खरीदी केंद्रों में सुरक्षा, साफ-सफाई और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों का असर अब गांवों में साफ दिखाई देने लगा है। खेती फिर से सम्मान और समृद्धि का माध्यम बन रही है। किसानों का विश्वास मजबूत हुआ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ खेती-किसानी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान आत्मनिर्भर बने, हर गांव समृद्ध हो और छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी कृषि राज्यों में अपनी नई पहचान स्थापित करे।

खुशहाल किसान • समृद्ध गांव • मजबूत छत्तीसगढ़

संवाद-48628/1

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.